[श्री मधु लिमये]

कानूनी काम हो रहा है इसकी ओर से सरकार अपनी आखें क्यों मूंदे हुई हैं ? क्या इनको पता नहीं है कि जो जमीन बेची गई है पूंजीपतियों को इसमें उन से अंडर दी टेबल भी पैसा लिया गया है।

एक आवश्यक सवाल लीज पर दी गई है।

श्री मधु लिमये . ठीक है 99 साल की लीज है । छः परसेंट या किसी और हिसाब से अनुमल लीज तैयार करते हैं। लीज कहिये, कुछ भी कहिये लेकिन केन्द्र की जो मिलकियत है उस पर राज्य आक्रमण कर रहा है, पूंजीपतियों को जमीन दे रहा है और इतना ही नहीं उस में पैसा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। सको संसद कभी बरदाश्त नहीं कर सकती है । मन्त्री महोदय इसका खुलासा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर को इसको भेज दिया जाएगा।

श्री मधु लिमये : अब कुछ नहीं कहेंगे । कई दिन हो गये मैंने नोटिस भेजा था ।अपने दफ्तर से पूछे कल मैंने इसकी कापी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरफ से तो आज ही हुआ है । इसको भी आपने ऐसा बना लिया है जैसे कालिंग अटेंशन हो । इसको मिनिस्टर के पास भेज दिया जाएगा ।

श्री मधु लिमये . चोरी हो रही है और ये चुप बैठे हैं ।

13.32 hrs

GENERAL BUDGET, 1974-75—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER : The time left is just enough for the Finance Minister to reply. But, one or two Members from both sides of the House can be accommodated. The Finance Minister will reply at 3 P.M.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH) : The Finance Minister may be called at 3.30.

MR. SPEAKER : The members will welcome it because they want more time to speak. The Finance Minister will be called at 3.30.

Shri Vidyalankar, who was on his legs, may continue.

श्री अवतार सिंह विद्यालंकार (चंडीगढ़) : कल मैं कह रहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जब तक मौलिक परिवर्तन नहीं होता तब तक हम बहुत सी समस्याओं को हल नहीं कर पायेंगे । मैं यह भी कह रहा था कि हमारे यहां एक समानान्तर ब्लैकमार्किट का रुपया चल रहा है । इसके संबंध में इस बजट में कोई चर्चा नहीं है । मुझे खुशी है कि कल राज्य सभा में उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने इसकी तरफ इशारा किया और विश्वास दिलाया कि इस ब्लेकमनी की रोकथाम करने के लिए वह प्रयत्न करेंगे ।

13.34 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ये प्रयत्न क्या होंगे यह हम को पता लगना चाहिये । ये बजट में जो संकेत इसका है उसके सम्बन्ध में क्या प्रयत्न होंगे कुछ नहीं कहा गया है । बिना प्रयत्नों को जाने हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि कारगर ढंग से आप इस समस्या का समाधान कर लेंगे। अगर आप यह समझते हैं कि 97 ½ परसेंट से घटा कर 77 परसेंट कर को कर देंगे तो ब्लैकमनी की समस्या हल हो जायेगी तो मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा और इस में आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी । जो लोग ब्लैकमनी में डील करते हैं उनको इसकी आदत पड़ गई है और वे आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं । हमें कुछ कारगर प्रयत्न इस दिशा में करने पड़ेंगे।

समाजवादी नियंत्रण जहां पर असफल हो वहां पर उसका इलाज यह नहीं है कि हम कदम पीछे हटा लें और समाजवादी जो हमारे मेजर्स हैं उनको ढीला करदें । उसका उपाय यह है कि हम और भी ज्यादा समाजवादी मेजर्स लें और इन उपायों का आश्रय लें। मैं मिसाल देता हूं । कल वित्त मंत्री के भाषण से इस बात का इशारा मिला है कि गेंहूं के व्यापार के बारे में जो नीति है उस में ढील देना चाहते हैं और उसको तबदील करके शायद वह सरकारी

हाथों से प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। जिस तरह चीनी और इस्पात के सम्बन्ध में दो भाव रखे गये हैं यह जो तरीका है यह हमें कुछ बहुत आगे ले जा सकता है अगर हमने दूसरी चीजों में भी इसको लागू किया इसको मैं नहीं मानता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि कीमतों की बढ़ोतरी के कारण जो संकट पैदा हो रहा है या दूसरे संकटों के कारण जो समस्यायें पैदा हो रही हैं, उनका यह कोई इलाज कर सकेगा। मैं समझता हू कि हम को समझ लेना चाहिये कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था जिस पर आज हम चल रहें है वह अन्तिम हमारा लक्ष्य नही है बल्कि वह एक सीढ़ी है एक साधन हैं, एक ट्रांजीशनल चीज है और अन्तिम हमारा लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था कायम करने का है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था हमारी आखिरी मंजिल नही है।

सरकार के जो अनप्रोडक्टिव खर्चे है उनको भी आपको कम करना होगा। ऐसे बहुत से खर्चे है जो अनप्रोडक्टिव हैं और उनको आपको देखना होगा।

सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण मे भी थोड़ा परिवर्तन आना चाहिये सोचने का उनका तरीका बदलना चाहिये। मैं चंडीगढ़ की मिसाल दे कर इसको बतलाना चाहता हू। वहा पर मकानो की किल्लत है। करीब दस हजार लोगो को वहां मकानों की आवश्यकता है। जब इसके बारे में कहा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि हमारे पास रुपया नही है। लेकिन दूसरी तरफ 21 लाख रुपये की लागत से वहां फ्लाई ओवर बन रहा है जिस की आज कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां इतना ज्यादा ट्रैफिक नही है। यह 21 लाख रुपया बच सकता था। सात लाख रुपये की लागत के आप वहां स्केटिंग रिंग कायम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग बेघर हैं। क्या इस तरह के जो खर्चे हैं इनको न करके लोगों के लिए जो बेघर हैं मकान नहीं बन सकते हैं? इनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। इस तरह से हमारी इनटेग्रिटी और ओनेस्टी पर शक करते हैं।

मैं चाहता हूं कि इस बात का निश्चय ठीक तरह से करना चाहिए कि कौन सा काम आवश्यक है और कौन सा नही है – किस को प्रायर्टी देनी चाहिए और किस को नही।

इन शब्दो के साथ मै बजट का समर्थन करता हू।

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think it would be true to say that this budget is more realistic than any of the other budgets that the Finance Minister has presented. But I do not think it is possible to sustain his claim that it is either growth-oriented or anti-inflationary. I would give two instances in respect of each to explain my point.

The Finance Minister has decided to extend the development rebate for one year. Whatever machinery or equipment that has been ordered prior to 1st December, 1973 would be eligible for it, provided it arrives here before 31st May, 1975. While it is perfectly correct and proper that a date limit should be fixed, the date of delivery is not dependent on the date on which the order is placed or the desire of the party who has placed the order. It would depend upon the supplier and the country to which he belongs. Suppose you place an order for a ship in the United Kingdom, it may take more than two to three years for delivery. If the same order is placed on Japan, the delivery might be possible within a year or 18 months. Therefore, while insisting on 1st December, 1973 as the date for placing the order, I would have thought the Finance Minister would have allowed greater flexibility in regard to the arrival of the equipment or ships which have been ordered prior to that date. That would certainly have been more growth-oriented.

Then I come to the anti-inflationary aspect of the budget. What can be the result of the numerous excise duties that have been imposed under the Finance Bill? Excise duties on those items which directly affect the ordinary man can only have an inflationary effect. Why is it necessary to

[Shri H. M. Patel]

impose these duties in this particular year when it is most important that every possible step should be taken to contain inflation and not do anything that may increase the growth of inflation? Excise duties have been imposed on many items which have a direct impact upon the ordinary man. In fact, the excise duties even on luxury goods lead to price rise of other items which are not affected by such imposition, because of the climate that is created by the mere imposition of excise duty. So, here again the step taken is not only not anti-inflationary but is directly inflationary. By this budget even the postal tariff has been raised substantially and it will certainly affect the smaller man. Postal service is clearly a social service and the aim of the Government should be to provide the social services at the lowest possible price, even if it means that a loss has to be incurred. Any rise in the postal rates will certainly result in inflation.

Then, while a Budget, of course, cannot be expected to remedy all wrongs, I think it can certainly draw pointed attention to and insist upon Government policies to be so directed that black market and other activities can be reduced. One of the things that helps inflation most is corruption. What is the direct cause of corruption? It is the controls. The Government should realise by now that a great many controls are not really necessary at all. In fact, if we were to have a complete and thoroughgoing review of the controls now in operation, we would find that we could dispense with great many controls without materially affecting the efficiency in regard to anyone of the items so controlled and, yet, this one step would eliminate, to a very large extent, corruption and corrupt activities. Undoubtedly, there are some controls which may still be found to be essential. They can be retained. If the number of controls are reduced, it may be possible also to ensure that the controls that are retained thereafter could be enforced in a more effective manner.

I would also like to draw the attention of the hon. Finance Minister to this fact. Has he really satisfied himself that his taxation machinery, tax-collecting machinery, is functioning with the maximum possible efficiency? Does he give the attention that is due to the Audit Reports and the Public Accounts Reports on these matters? If he has done so, then he would have really found where it was necessary and possible to improve the taxation machinery long before. I would urge upon the hon. Finance Minister to go through these Reports with the greatest possible care and see how far it rests in his hands to improve the machinery.

For instance, you take the Income-tax Officers, the calibre of the Income-tax Officers, the recruitment of Income-tax Officers, the qualifications that they should have, their salary scales, for years these questions have been settled, questions of fixing and determining their salary scales and other things. When you give enormous powers in their hands, when it lies within their hands to recover lakhs of rupees, to pass orders which affect lakhs of rupees recovery, you should have found it necessary to ensure that those officers are of the highest calibre possible and also to ensure that their remuneration is fixed in an adequate manner. What do you do instead? Complaints regarding their salary scales, their promotion prospects, etc. remain pending for years. I understand that some steps have been taken to improve them. But they are hesitant steps. Have these questions really been taken in hand with the degree of urgency that is necessary?

Again, you consider the number of cases that are delayed in implementation, assessments not completed and recoveries not ensured. All these matters are dealt with in considerable detail in the P.A.C. Reports. I hope, the Minister listening to these remarks of mine will make a point of studying these Reports. I know how industrious she is. I hope, she will assist the Finance Minister in this particular aspect and thereby ensure substantial improvement in the recovery of direct taxes. If that improvement occurs, I have not the slightest doubt that it would not have been necessary for

the Finance Minister to impose additional taxes to the extent of a paltry sum of Rs. 100 crores or Rs. 200 crores. I am sure, much larger sums could have been recovered in this way.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Most of the speakers are now from the Congress benches I have been requested by the Whip to allot seven minutes to each so that we may be able to accommodate all or most of them.

Dr. Govind Das Richhariya.

डा० गोविन्द दास रिछारिया (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, आज की परिस्थिति में वित्त मंत्री जी ने जो संतुलित बजट पेश किया है निश्चित तौर से वह उस के लिए बधाई के पात्र हैं । किन्तु उनको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आज देश के सामने और भारत सरकार के सामने सब से बड़ा प्रश्न महगाई का है । उनके बजट की सफलता इसी से आंकी जायेगी कि वर्ष के अंत तक महगाई पर कितना काबू उन्होंने पाया है । इसके ऊपर भारत सरकार की और बजट की सफलता निर्भर होगी । निश्चित तौर से महगाई के लिए मोटे-मोटे दो काम आवश्यक है । सबसे पहले उत्पादन को बढ़ाना और दूसरे जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनका वितरण । आज यह सारे देश में महसूस किया जाता है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ जो वितरण की व्यवस्था है वह सही नहीं है । जिन हाथों से वितरण होता है वह ठीक नहीं हो पाता है । उसमें भ्रष्टाचार और दूसरी चीजें होती हैं । निश्चित तौर से आज भारत सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वितरण के लिए वह कौन सी मशीनरी का प्रयोग करे ? किस तरीके से जो वस्तुएं पैदा होती हैं उनका वितरण सही तरीके से, समान तरीके से समाज के प्रत्येक वर्ग तक और खास तौर से उस वर्ग तक पहुंच सके कि जो उचित है, जो गरीब है । उसके लिए चाहे समाज को शामिल करते हुए कोआपरेटिव के आधार पर व्यवस्था बनाई जाय या जो भी उचित हो वह किया जाय लेकिन एक इस तरह की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिस पर कि नागरिकों का विश्वास हो, जिस से देश के रहने वालों को मालूम हो कि जो चीज पैदा हुई है वह सही तरीके से हम तक आ गई है ।

जहां तक उत्पादन का सवाल है, निश्चित तौर से उस के दो स्थल हैं । पहला है भूमि और दूसरा है कारखाना । भूमि का संबंध विशेष तौर से कृषि उत्पादन से है । इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है भारत सरकार की और वित्त मंत्री जी को भी भूमि के संबंध में जितने भी भूमि वितरण के कानून अब तक बने हैं मेरा ऐसा ख्याल है कि वह सारे देश में कार्यान्वित नहीं हो सके हैं । मैं अनुरोध करता हूं वित्त मंत्री जी से कि वह एक तारीख सारे देश के लिए निश्चित कर दें कि इस तारीख तक सारे देश में भूमि वितरण की व्यवस्था निश्चित रूप से लागू हो जानी चाहिए । दूसरा जो सब से आवश्यक काम है वह है भूमि सुधार का । हमारे देश में आबादी बढ़ रही है । हमारी जमीन का रकबा उतना ही है । तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम भूमि सुधार को बड़ी तेजी से लागू करें । मैं देखता हूं कि सारे देश में जितनी भी भूमि सुधार की योजनाएं हैं वे युद्ध-स्तर पर लागू नहीं की जाती हैं । चाहे भूमि संरक्षण हो, चाहे भूमि को समतल करने की बात हो, इनको युद्ध-स्तर पर चलाने की आवश्यकता है । इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

इसी तरीके से कृषि उत्पादन के लिए सब से आवश्यक है सिंचाई । सिंचाई का प्रतिशत भी हमारी पंच-वर्षीय योजना में अधिक नहीं रखा गया है । इस पर सोचने की और पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । लघु सिंचाई के द्वारा, मध्यम सिंचाई के द्वारा और बड़ी सिंचाई योजनाओं के द्वारा पांचवीं योजना के अंत तक जितनी सिंचाई हमको प्राप्त होनी है वह हमारी आवश्यकता के लिहाज से कम प्रतीत होती है । इसको किस तरह बढ़ाया जा सके इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है । इसी के साथ साथ सिंचाई में जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाना चाहिए । पानी का विवाद जहां भी है उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आज देश की कई नदियां ऐसी हैं जिनके पानी का कोई उपयोग उन के ऊपर विवाद होने के कारण नहीं हो पाता है और उनका पानी सब समुद्र में चला जाता है । सिंचाई योजनाएं विवाद के कारण कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं । जल्दी से जल्दी ये मामले तय हो सकें इसके लिए जो सुझाव है कि केन्द्र का अधिकार उस पानी के ऊपर हो जो पृथ्वी पर आता है या उन नदियों के ऊपर हो जो दो या दो से अधिक प्रदेशों में

[श्री गोविन्द दास विजारिया]

बढ़ती है, इसके ऊपर बहुत बार कमेटियों में और सदन में भी चर्चा हुई लेकिन मैं आज तक उस को कार्य रूप में परिणित नहीं किया गया। यह बहुत आवश्यक है कि देश का जो पानी है उस के ऊपर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो जिससे ये सारे विवाद निपट सकें। इसी तरह बीज खाद या कृषि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले औजारों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक कारखानों का सवाल है, आम तौर से यह शिकायत रहती है कि जितने भी कारखाने सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं वे घाटे में चल रहे हैं। आप विशेष विचार करें कि क्या वजह है जिससे सरकारी कारखाने घाटे में चलते हैं। यदि इन कारखानों में जितने श्रमजीवी हैं, श्रम करने वाले लोग हैं उनको भागीदार बना दिया जाय, उसके प्रशासन में और उसके उत्पादन में उनको भागीदार बना कर रखें तो निश्चित तौर से उन के अंदर उत्साह पैदा होगा। उनके अंदर एक इस तरह की लगन पैदा होगी और वह ज्यादा काम करेंगे। उससे कारखाने का उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश में योजनाओं को विकास का माध्यम बनाया है। लेकिन योजनाओं का समन्वय देश के नागरिकों के साथ नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारी जितनी भी योजनाएं बनें उसमें जो हमारे देश के, प्रदेश के और गांवों के नागरिक हैं उनका एक समन्वय हो। इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिएं जिसमें प्रदेश निवासी यह समझें कि देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, उनके जिले के और गांव के विकास में उनका अपना हित है और उनको उस में सहयोग करना है? इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि हमारी योजनाएं इस ढंग से बनेंगी और उसमें विशेष ध्यान इस बात का रखा जाएगा।

तृतीय पे कमीशन की रिपोर्ट जो आपके सामने पेश हुई आपके सभी विभाग और सभी वर्ग के लोगों के लिए वह पूरे तौर से अभी तक लागू नहीं की गई है। फर्स्ट क्लास के कर्मचारी अभी तक उससे लाभान्वित नहीं हो सके हैं। उस तरफ भी शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिए क्वार्टर बनाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो आप एवार्ड्स देते हैं कर्मचारियों को उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं जिसमें कि आप कुछ दूर कर सकते हैं। उसमें आप कुछ बचत कर सकते हैं। जो आपके कर्मचारी पहले से मकान के लिए हैं उनके लड़के बच्चे नौकरी में लगते हैं तो वह भी यह कह करके रख देते हैं कि हम अपने माता पिता से अलग रहते हैं। इस तरह से आप का बहुत रुपया बेकार चला जाता है। इसे की बचत की जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR (Joynagar) : I rise to support the Budget of the hon. Minister, Shri Yeshwantrao Chavan. However, I do not share the view that it is a very bold budget as expressed by some of our colleagues. But I would say that there is a pragmatic approach and a truthful admission of the facts and failures.

The only thing that he is trying to create is to bring a fresh air in the field of investment. It is true that by giving tax relief particularly in regard to income tax, by reducing it to 77 per cent from 97.75 per cent, certainly he is trying to get fresh air in the investment field. So long he was Finance Minister—he has been Finance Minister for the last four years—he has tried to bring that air through the ventilation holes, but this time he was courageous enough to open some channels, that is, some doors or windows to bring that climate. But I am in doubt whether it is possible at all because so much indirect taxation has been imposed. I doubt whether that climate can be created at all Unless he creates enough resources, how will he tackle this problem of unemployment or the removal of poverty or the achievement of self-reliance? Would it be possible by merely giving a tax relief from 97.75 to 77 per cent? Will it increase the investment in every field? I doubt about that suggestion and about the decision which has been taken by the Finance Minister.

श्री ललेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी पटना से खबर आई है। . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not now.

SHRI G. P. YADAV :**

**Not recorded.

MR. DEPUTY SPEAKER : This will not go on record. It is against my nature to suppress any Member. I don't want to do it. But there are certain rules in this House ; we are in the midest of one discussion ; and Hon. Memebr is on his legs. To come and interpose something else in between is a complete violation of the rules. Now certain things have been happening there which are not in accordance with parliamentary practices, but if you want me to violate all these practices here, then where do we differ from what is happening there ? Therefore, I would request you ot resume your seat. We shall see what happens, but please don't disturb the discussion now, and kindly sit down.

14 hrs.

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR : My time is very limited and I have an intention to say something more but I now concentrate my energies to ask some clarification from our Finance Minister and the Dy. Finance Minister present here. I want to say something about the capital formation of the country. It is known to everybody that surplus over consumption and saving over expenditure, goes to capital formation. Will the tax proposals yield that climate in which we will be able to attract savings ? I feel that it is an impossible proposition. Every year the prices are rising higher and higher. Just now one of my colleagues referred to the incidents of Patna. This is mainly due to the cause of inflation and the price rise. Of course I do not fully agree with his views. But I want to know how we could tackle this problem.

Due to the rise in prices we will not be able to produce enough which we want to do. Our agricultural sector has been adversely affected due to price rise. There is no possibility of increasing fertiliser production. As you know we are going to have deficit to the extent of 5 lakh tonnes in fertilisers. That means, 50 lakhs tonnes of agricultural production will be lowered automatically. This is the position, Sir.

The industrial climate is also stagnating as has been stated by our Finance Minister in the Economic Review.

There is no chance of prices coming down. Raw materials are scarce. The prices are rising day by day. Imported materials are getting more and more costly. In these circumstances I want to know how we could increase the production in the agricultural sector, and also the industrial sector.

Sir, unless we increase production in these two sectors there is absolutely no hope, there is no ray of hope at all, to give any consolation to the poor people of our country.

We are being criticised inside and outside. Even the housewives do not spare us. There has been 100 to 300 per cent increase in prices. There has been increase in price in respect of edible oils, in respect of mustard oil, in respect of coconut oil and even sugar. What is the explanation for this ? How we can lower down the price rise ? If we can bring down the price, can we at all stabilise the price ? This is the basic question which I request the hon. Finance Minister to answer.

So far as inflation is concerned, I wish to say something. How can we deal with this problem posed by increase in inflation ? There is no hope which can be given by the Finance Ministry to control or to check inflation at this rate even. Last year we had seen this, that we had to depend upon printing presses for printing notes for more circulation of money into the market. And this year also there is no hope of curbing it because this year we have been compelled to increase the amount from Rs. 100 crores to Rs. 220 crores in respect of relief measures which is a single case in the field of expenditures. This is only one of the many examples. No doubt it is a dire necessity to increase the amount but at the

[Shri Shakti Kumar Sarkar]

same time we should admit that we failed to curb the tendency of inflation.

How can we deal with inflation and deficit financing? This, I want to be clarified and I want to know that from our wise and experienced Finance Minister.

As regards national income, in this Explanatory Memorandum, he said that a significant growth rate in national income is seen. I do not know from what sources we will come to know of this. So far per capita income is concerned, it has gone down to such an extent that we can see it with open eyes. Same is the case with regard to gross national product. There is no answer given to this even in his Explanatory speech. So, I want to know what is the position with regard to gross national product at present and what is the per capita income? How can he justify that statement that a significant growth is seen in the national income. Sir, as a student of Economics, I know that the national income has not been increased substantially. Rather, that has been decreased.

As regards eradication of poverty and unemployment, the Minister has categorically said that we will achieve this twin objectives, that is, removal of poverty and self-reliance—in this country. How can we achieve it? Everything is being eaten up by the price rise. There is no clear answer to this from the Government. If somebody puts a question regarding the burning problem of inflation, a curious explanation is given. Somebody says that the deficit financing is the cause for this inflation somebody else says that inflation is due to drought and floods. Someone says the inadequate performance by Government and increasing unlimited expenses over estimates on plan and non-plan projects. But if you want to fix up the responsibility, a curious explanation is given he is doing his best shifting his responsibility from his shoulders to others.

I want to refer to one small story which comes to my mind. Once an Inspector of Schools visted a school. Entering Class X he asked the first boy as to who broke the *Har Dhanu*. Everybody knows that this is a story from Ramayana. He could not reply and said that he had not seen as to who had done this mischief. Cunningly he shifted his ignorance to the class teacher. The answer given by the teacher was that he was only busy in his own affairs and he had not done this mischief. He had no time to know who had done this mischief. He then referred that to the headmaster. Curiously, the inspector went to the headmaster and asked him who broke this *dhanu*. He also said that he was so busy with his own administrative affairs he could not see to the matter himself to be able to give any answer to this. He shifted that to the Secretary Then the Secretary was called and the very same question was asked. He also at once shifted his responsibility to the Managing Committee Like this, we are shifting our responsibility but nobody is answerable for any problem. If that is so, who is going to solve the problem.

We stand for eradication poverty; we loudly advocate eradication of poverty. But, nobody knows the solution for this. The difficulty is this. We are not taking the people into confidence for this purpose. Unless we involve the people, there is no scope for implementing the plan. The bureaucrats alone cannot do this. Unless you take the people into confidence as also their elected representatives—the M.Ps. and M.L.As.—how can you expect the desired result of meeting the minimum needs of the people as envisaged by the Planning Commission? We would be constantly lagging behind. So I would request the Minister to see that these minimum needs programme as envisaged by the Planning Commission are carried out with the help of the people of this country by involving them in the implementation of the Plan.

With these words, I support the budget.

DR. KAILAS (Bombay South) : I support the budget proposals and congratulate the hon. Finance Minister on presenting this much-dreaded budget in a balanced manner in a difficult situation like very

high price rise and very low industrial growth.

Inflation has played a major role in the price rise in the country. The Finance Minister and our leaders say that inflation is being tackled from many fronts. I do not know how it is going to be fought. Until and unless we apply our mind and take some positive actions, it is very difficult to fight inflation.

I was thinking that the budget this year would perhaps be a surplus one so that we could show to the world and to our countrymen that in spite of the high price rise, we could perhaps not tax the people so much but would see that our house was in order.

We are spending crores and crores of rupees on wasteful expenditure, and we are spending crores of rupees on our public sector undertakings, but we never think in terms of giving them the foreign exchange required for import of raw material in time or of allowing the STC to earn crores of rupees worth of foreign exchange. We have seen how they have dealt with buying of paper. Paper was available in the world and we had the contract also, but we would not catch that proposal or follow up the agreement which had been entered into, because perhaps powers were not given to the men in charge there, and the result was that we missed the bus.

The same thing happened with regard to wheat and rice also. My intention in telling all this was that even if it meant the bearing of extra burden by the country, we could perhaps have avoided this type of deficit financing or inflation to the tune of Rs. 125 crores this year because through export we could have earned foreign exchange almost equal to this amount.

The Finance Minister has rightly said that 1974-75 is going to be a difficult year. It is for the countrymen to know why he has said so. What is the role of the leaders or the elected Members of the Assembly and Parliament? How are they to tell the people that they must sacrifice? Today everybody is crying that they are not getting sugar, they are not getting cement, they are not getting steel and so on. If only we could do without steel, cement and sugar and some such articles and export all of these, perhaps we shall be able to do some justice to our existence and to the country. Hence, we should be able to tell the people that they would be helping the country by sacrificing a little for some years. Rather, this is not sacrifice but proof of our love towards our motherland.

Since only seven minutes have been allotted to me, I shall suggest briefly what should be done to avoid inflation without going into detail of these suggestions. Firstly, there should be improved labour-management relations to bring about more production, because production is the answer to the present situation. Today everybody talks, including the Prime Minister, that there should be more production. I would point out that this is a political question. Our labour class is so meek and kind and good and they are more patriotic than anybody else. If only the political leaders who have gone into the labour field could keep quiet, things would be better. Look at what has happened in the railways. I say that it is the political leaders who are troubling the country more than the labour class. The labour class is being used as a stooge in their hands. I would request the Prime Minister to kindly call all the labour leaders and ask them to have a truce. Let there be not a war, in labour field but let there be some truce for some years to come.

Then, administrative expenditure should be reduced and discipline should be brought into the clerical staff and higher management staff. No mind is being applied to the question of overstaffing and overtime allowances. I have seen with my own eyes how in the nationalised banks in my constituency, for the whole day, the staff are chit-chating and wasting time and start their work after 5 p.m. just to get their overtime. The overtime bill and Medical bill perhaps are much more than even their pay, especially in Nationalised Banks, Rali-

[Dr. Kailash]

ways, and other Public Undertakings under Tourism and Civil Aviation.

The Deputy Minister for Finance is here. I hope she will not mind it or feel it if I say that her PA or steno or typist is getting one and half times the regular pay as overtime allowance. Perhaps the Ministers being busy, do not keeping their time. They call their staff and ask them to work late and in this way they have to work overtime. This can be curbed but the Ministers enjoy giving them overtime. If Ministers can set an example by not allowing their staff to draw overtime, perhaps the country will be a much better place to live in and others will follow suit.

Then I would suggest that more funds should be allotted to Air India and Indian Airlines to attract more tourists. This underaking must give incentives to those who wish to visit India as tourists. Today four lakh people are coming as tourists. If some such incentive like reduced fare and other facilities of stay and transport are given to Air India and IA, perhaps more tourists could be attracted. The country will earn crores of rupee if this is done

Then the duty-free shops are there I am very sorry to say this. I have seen with my own eyes that Indian goods are not available there. When foreigners ask for Indian goods, these are not available. They ask for Indian wines; they are not available. They ask for Indian cigarattes; they are not available. Please see that in the duty-free shops, plenty of Indian goods, for which there is craving, are available.

Then the development rebate should be extended to two years and not for one year. This will enable those bussinessmen or industrialists to lay plan ahead. The period of one year allowed is not enough and the benefit of this concession will not bring the desired results. Why I say so, as for change over from mobil oil to coal for transformers, it is not so easy as to be completed in one year. But if you announce now to give time for two years, things will move swiftly and the country will gain.

Then as for the exemption limit of income-tax, it should be raised from 6,000 to 7,500. The value of the rupee has gone down so much that this should be done. Also the work of the lower officers in the income-tax department is so much that they cannot tackle the big fish adequately with the result that tax arrears are mounting up Hence the exemption limit should be raised as I have suggested.

Then 'credit squeeze' was an expression which was used by the general public. Really speaking, it should have been a rational credit plan. But unfortunately, it has been known as credit squeeze or credit freeze. This wrong impression should be removed from the minds of the people I think there is something irrational in this and hence these words have come into use and people think that it is a freeze on development and on production. though the Reserve Bank has rightly brought out this measure for regulation of credit very nicely.

Then there should be demonetisation of 100 rupee notes and of above denomintions.

One thing more. This will be news to the House and I wish it gets a little publicity. Crores of rupees worth of bank drafts are moving in "benami" names The sender knows to whom they are sent and that person also gets the money. In this way, crores of rupees of black money are moving from one place to another. If a raid is conducted on a day on all the banks, nationalised, foreign and other banks, simultaneously, I am sure the evil of the black money can be reduced to some extent.

श्री जागेश्वर प्रसाद यादव . उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 340 के अन्तर्गत निवेदन किया था उसके बारे में आपने क्या किया ?

MR. DEPUTY SPEAKER : We have already spent so much time discussing this

question. I have seen your notice. I think it was decided earlier that the Home Minister would make a statement tomorrow; I think the Speaker had generally indicated that he was not averse to a discussion after that.

श्री कमलेश्वर प्रसाद यादव : दो बातें थी। अभी भी गोलियां चल रही है और कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 21 तारीख को बिहार विधान सभा स्थगित कर दी गई है जबकि 21 तारीख को चुनाव है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि बिहार का गफूर मंत्रिमंडल बिल्कुल असमर्थ है समस्याओं को टैकिल करने में इसलिए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टूडेन्टस काम को, जो उनकी बिल्कुल साधारण सी मांगे हैं उनको सरकार नही मानती है। उन्होंने साधारण सी मांगें की तो उन पर गोलिया चलाई गई। (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: There is nothing new in this. That is enough.

SHRI DHARNIDHAR DAS (Mangaldai): Mr. Deputy-Speaker, let me begin with the last sentence of the Budget speech of the Hon. Finance Minister; he says:

> "The social and economic problems that we currently face can be resolved in the long run only in the framework of a rapidly expanding economy with socialist objectives. I trust this budget is one more step in that direction."

In the background of our national economy, we have to consider the budget from the standpoint: how far this budget or the other budgets passed in this House have led to a socialist objective. This is the fourth budget placed before this House by Chavanji, after mid-term elections which returned the Congress Party to power with a massive majority in this House. People supported this party because it was this party that promised the people the removal of poverty and the establishment of socialist economy. There was mass upsurge at the time of the elections and earlier when the banks were nationalised. People thought that this party under the leadership of Prime Minister Indira Gandhi would liquidate capitalism and establish socialist economy. It means the ending of exploitation and removal of inequalities and poverty. Our departed leader Pandit Jawaharlal Nehru said: "Unless the process of socialism is speeded up, people would become impatient and discard peaceful methods of economic transformation." This is what is happening in the country today. It is because of the paradox in the capitalist economy. On the one side we see vast numbers of people begging for food, starving; they have no purchasing power. On the other hand we are talking of conspicuous consumption of a few people in the affluent class. So there has developed a revolutionary situation in the country. I am therefore saying that we have not taken the economy in socialist direction. During the last three years monopolies have increased. We nationalised banks. These and other financial institutions which we have at our disposal are financing monopolies as before. So, we have been complaining all the time that our whole national economy is in the grip of 75 monopoly houses. The statistics furnished by the Government shows that these monopolies are getting more loans from the nationalised banks, from LIC and other public financial institutions. Unless we break the stranglehold of these monopolies and unless we take over these monopoly houses, we will not be able to establish a socialist in this country.

Another matter on which I wanted to lay stress is this. Inequalities among various sections of the people, which we wanted to remove, have been increasing. Even among the salaried class, if we look at the salaries which people at lower levels get, we find that 50 per cent of the Central Government employees get a salary between Rs. 100 and 149. Only 3 per cent of the employees get Rs. 500 and above. So, there is inequality even among the salaried class. Again, in our economy if we look at the post tax income, we fined a difference of one to hundred between the lowest income and the higest income. In

[Shri Dharnidhar Das].

this way, inequalities are increasing every year.

Now, this maximum marginal rate of taxation has been reduced from 97.75 per cent to 77 per cent. The argument advanced is that there will be less tax evasion. But, this shows a weakness on the part of Government that they are not able to control tax evasion, they are not able to force them to pay taxes, and therefore, they are giving them concessions and reliefs. In the socialist countries, they do not depend upon taxation. There, the main source of revenue is not from taxes, but, it is from the socialist and other collective or cooperative enterprises. Here, in our country, where we depend purely on taxes, as our source of revenue, to that extent, we are going in the capitalist direction. This is one indicator of the capitalist character of our economy.

Now, about price rise. It is the nightmare of the common people, their main problem. How can be reduce the prices? Price-rise is profit-rise. When there is price rise, there is also profit rise, on which Government have no control. Last year, the Finance Minister talked boldly about the public distribution system. Now, this system is not working.

14.29 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

In this connection, I would like to cite the example of Assam as giving a lead to the whole India. There, we have taken over the rice and foodgrain trade, while eliminating wholesale traders in rice trade. We are distributing rice and other essential commodities through cooperatives. If we really want to bring down the prices of essential commodities, then, we have to strengthen the public distribution system. Procurement and distribution should be done through cooperatives and cooperatives alone. We have to eliminate the private traders both at the procurement and distribution points.

I would also like to draw the attention of the Finance Minister that because of inadequate supply or lack of supply of essential commodities to Assam, the distribution of essential commodities through cooperatives has suffered a set-back. Perhaps, there is only one way to do it. All consumer goods industries should be nationalised. The entire distribution system must be channelled through people's cooperatives. Then only we will be able to ensure the supply of essential commodities to the people at reasonable or fair prices. Otherwise, if we leave the production and distribution to remain in the hands of capitalists, this price rise will go on and there will be a veritable revolution in the country, which we would not be able to face with all the forces at our command. Therefore, to bring down the prices, we must nationalise all consumer goods industries, particularly of essential commodities and strengthen the distribution system through people's cooperatives. The Central Government must ensure the supply of essential commodities, particularly to Assam, where we have already set up a network of cooperatives for procurement of rice, paddy, etc and also for the distribution of essential commodities.

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर) . जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है उसका मैं स्वागत करती हूं और इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूं। बड़े अच्छे ढंग का बजट उन्होंने बनाया है और पेश किया है।

मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगी। वहां पर हरिजनों और आदिवासियों और भूमिहीनों की संख्या बहुत अधिक है। जिनको अभी तक वहां जमीनें मिली हैं उनके पट्टे भी बड़े-बड़े लोगों ने जा कर कैंसल करवा दिए हैं। इस ओर आप ध्यान दें। उनके सामने जमीन की, घर की, रहने की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। इनका वहां नितान्त अभाव है। देहात का जो किसान है उसके पास न जमीन है, न सिंचाई के साधन हैं, न बीज है, न खाद है। इन सब चीजों की ओर आप ध्यान दें। और यह कहा जाता है कि सिमेंट हमारे पास नहीं है इसको मैं नहीं मानती हूं। सिमेंट काफी है। लेकिन अफसर लोग मिल मिला करके रातों रात उसको ब्लैक में बेच देते हैं। व्यापारी लोग उनसे मिल कर बेच देते हैं। [illegible]

ईमानदार हों तो ऐसा नहीं होगा। मैं यह नहीं कहती हूं कि सभी अफसर और कर्मचारी बेईमान हैं। ईमानदार उनमें लोग हैं। लेकिन जो नहीं हैं उनको आपको देखना होगा। आज तीस रुपये बोरी सिमेंट ब्लैक में मिलता है। कहां से आ जाता है अगर सिमेंट की कमी है। आपने कंट्रोल इस पर कर रखा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। वितरण का तरीका सही नहीं है। चीनी, तेल आदि देश में काफी है। लेकिन रातों रात, चीज को ब्लैक में बेच दिया जाता है, बारह बजे बेच दिया जाता है। जिन अफसरों के हाथ में चार्ज है वे सही तरीके से वितरण नहीं करते हैं और ब्लैक में व्यापारियों को दे देते है। चीनी वही जो कंट्रोल की है ब्लैक में जा कर चार रुपये किलो बिकती है। डालडा जितना चाहिये आप ले सकते हैं ब्लैक में, तेल जितना चाहिये ले सकते हैं। यह वितरण का दोष है। अफसर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आपके जो अफसर हैं, जो पटवारी हैं वही देश का नक्शा पलटेंगे, इन्हीं के हाथ में सब चार्ज है, एम० एल० ए० और एम० पी० के हाथ में कुछ नहीं है। हम लिख कर देते हैं तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। इतनी लूटपाट मची हुई है कि क्या कहा जाए। जो ईमानदार अफसर हैं उसको रहने नहीं दिया जाता है, उसको बेईमानी करने पर मजबूर किया जाता है और जो बेईमान है, जिन के पास तीन-तीन कारें हैं, स्कूटर है वे आनन्द उड़ा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। आप कड़ा कदम कोई उठाएं। जगह-जगह झगड़े हो रहे हैं। वे सब मिनिस्टरों के कारण हो रहे हैं। मिनिस्टर लोग सही तरीके से इन चीजों को देखते नहीं हैं। वे आदेश नहीं देते हैं और अफसरों पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। अफसर लोग सही तरीके से काम नहीं करते हैं। मैं सभी अफसरों पर उंगली नहीं उठाती हूं। कुछ हैं जो ईमानदार हैं। लेकिन उन ईमानदार अफसरों को निकालने की कोशिशें होती है। सही काम करने वाला डिपार्टमेंट में रह नहीं सकता है।

आप महिला हैं। आपको ज्यादा अनुभव है। महिलाओं को पता है देश में क्या बीत रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं गई थी। महिलाएं कहती थीं कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है इनको आप देखें। हमें गल्ला नहीं मिलता, लाइन में खड़ी रहती हैं, तेल नहीं मिलता, घी नहीं मिलता। बेचारी कह रही थीं कि हम वोट नहीं देंगे जब तक इन चीजों का साधन नहीं किया जाता है। गावों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आज जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है उन के ट्रकों के ट्रक पांच सौ रुपया ले कर उठवा दिए जाते हैं। वही चीज बाजार में ब्लैक में मिलती है। चार रुपया किलो चीनी और दो रुपया किलो गेहूं मिल रहा है। इनकी ठीक व्यवस्था आप करें। अगर प्रान्तीय सरकार को लिख कर दिया जाता है या सेंटर को लिख कर देते हैं तो छः महीने तक वह चीज पड़ी रहती है, कोई देखने वाला नहीं होता है। आप कोई उपाय करें। ठोस कदम उठाएं। रंजिश न करें। हम आपकी सहायता के लिए हैं। जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

आजकल देहातों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वहां जीना बड़ा कठिन हो गया है। कैसे जा कर हम लोग वहां सेवा कार्य करें। चोर बाजारी, मार पीट, झगड़ा आदि वहां आए दिन होता रहता है। वहां इज्जत बचाना मुश्किल है। आप कड़ा कदम उठाएं। शासन ठीक से चले और व्यवस्था कायम हो। कांग्रेस पर जनता की अब भी आस्था है। जनता कांग्रेस के साथ है। लेकिन आप जनता के कष्टों को दूर करने की कोशिश करें। गल्ला कम है तो कुछ तो मिले। पाव भर ही मिले। लेकिन कई बार मिलता नहीं है तो हल्ला होता है। प्रबंध आपको ठीक से इसका करना चाहिये। भाव निर्धारित कर देने चाहियें ताकि व्यापारीवर्ग ज्यादा न ले सके। सारे भारत में यह भाव आ सके ताकि जनता में सन्तोष हो। प्रशासन अच्छी तरह से चलना चाहिये। बजट अच्छा है। कहने को तो बहुत सी बातें थी लेकिन चूंकि आप घंटी बजाते जा रहे हैं, इसलिए मैं समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री चिरंजीव झा (सहरसा) आज देश में मूल्य वृद्धि अभाव तथा वर्तमान प्रशासनिक संयन्त्र के सेवा उन्मुख नहीं है और अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण देश में अशान्ति रोष और क्षोभ व्याप्त है उस अवस्था में भी सदा की भांति बजट को देख कर हर आदमी यह सोचता है कि इस बजट के चलते आने वाले वर्ष में उसकी कैसी स्थिति रहेगी। इसे देखने पर अगर वह समझता है कि उसकी स्थिति अच्छी रहेगी तो वह आश्वस्त होता है और अगर समझता है कि स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो वह चिन्तित होता है।

[श्री चिरंजीव झा]

इसी विचार से मैं इस बजट पर अपने विचार आज प्रकट करना चाहता हूं।

स्वयं वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के प्रारंभ में हाल की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है

"दुनिया में कहीं पर भी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव हुए बिना, आसानी से नहीं हुए। इसलिए मुझे इस सब से घबरा उठने या अपने बुनियादी लक्ष्यों व उद्देश्य के बारे में शंका कर बैठने की कोई वजह नहीं दिखाई पड़ती। हमारे सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने कि वे पहले थे। हम अपने लक्ष्य हासिल करने में उतने ही कृत संकल्प हैं जितने पहले। हम गरीबी, अज्ञानता व बीमारियों के खिलाफ हथियार इसलिए नहीं डाल सकते कि यह लड़ाई आशा से अधिक भारी पड़ रही है, हालांकि हो सकता है कि परिस्थिति के अनुरूप हमें अपने साधन बदलने पड़ें।"

मूल्य वृद्धि की चर्चा करते हुए आगे उन्होंने कहा है

"मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इन उपायों के बावजूद कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।"

इसके साथ ही मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह भी स्वीकार किया है.

"1973 में औसत से अधिक खरीफ की पैदावार होने पर भी कीमतें नीचे न उतर सकीं क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में कीमतों में वृद्धि करने वाली कुछ दूसरी शक्ति सक्रिय रही।'

सभापति महोदय, मंत्री महोदय के भाषण के इस अंश के सिलसिले में मैं उनसे दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने परिस्थिति के अनुरूप साधन बदलने की बात कही है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या तात्पर्य है। क्या मैं समझूं कि मंत्री महोदय यह मानते हैं कि अंग्रेजी शासन से विरासत में मिला वर्तमान प्रशासन तंत्र हमारी समाजवादी पद्धति के अनुरूप नहीं है? क्या वह समझते हैं कि इस प्रशासनिक तंत्र को बदलना है? यदि ऐसा है, तो जितनी जल्दी इस में सुधार लाया जाये, इसमें परिवर्तन किया जाये और इस का पुनर्गठन किया जाये, ताकि हमारा प्रशासनिक यंत्र हमारे समाजवादी कार्यक्रम के अनुरूप हो, उतनी जल्दी हमारे देश का कल्याण होगा, और हमारे समाजवादी कार्यक्रम के प्रति भी न्याय होगा।

मंत्री महोदय ने कहा है कि खरीफ की पैदावार 1973 में अधिक हुई, लेकिन कीमतें बढ़ती गईं, और वह भी इस लिए कि कुछ शक्तियां इस बारे में सक्रिय रहीं कि कीमतें बढ़ती जायें। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब वह समझते हैं कि ऐसी शक्तियां हैं—और दरअसल वह हैं—तो उन के खिलाफ वह कठोर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। आज सारा देश हमारे साथ है। तो फिर उन शक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में हिचक किस बात की है?

आप जानते हैं कि जनता ने दो-तिहाई बहुमत हम लोगों का दिया है, जिन का नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही हैं—हम आशा और विश्वास के साथ कि हम गैर समाज-द्रोही तत्वों के खिलाफ निर्भीक हो कर कड़े से कड़ा और ठोस कदम उठा सकेंगे। लेकिन जिस जनता ने हमें इतने बहुमत से जिताया है, आज उसे खेद और दुख है कि उसने जिस आशा से हम को इतनी शक्ति दी, वह पूरी नहीं हो रही है।

सभापति महोदय माननीय सदस्य जानते हैं कि आज वित्त मंत्री को इस बहस का जवाब देना है और अभी मान और सदस्य बोलना चाहते हैं। अगर हम समय का न्यायोचित बटवारा नहीं करेंगे, तो माननीय सदस्यों को ही असुविधा होगी। मैं चाहता हूं कि सब सदस्यों को थोड़ा-थोड़ा समय मिल जाये। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में दें और वे पांच मिनट से ज्यादा न लें।

श्री चिरंजीव झा सभापति महोदय, मैं कुछ पायंट्स रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय माननीय सदस्य सब ठीक बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे सदस्यों को भी मौका देना चाहता हूं।

श्री चिरंजीव झा मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा

आज हमारे देश में लाखों शिक्षित तथा अर्द्ध-शिक्षित बेकार हमारे लिए एक समस्या बने हुए हैं। लेकिन उन का सवाल तो अलग रहा, तुर्रा यह कि सरकारी सेवा में नियुक्त लोग आज हमारे लिए सब से बड़ी समस्या बन गये हैं। देश की वर्तमान संकट पूर्ण स्थिति तथा आम लोगों की करदाताओं की दयनीय परिस्थिति पर रहम किये बग़ैर आये-दिन वे लोग हड़ताल करते हैं और इस तरह हमारी उत्पादन क्षमता को बर्बाद करते हैं, उत्पादन में रुकावट डालते हैं और हमें परेशानी में डालते हैं। बेकारों की समस्या अलग है, लेकिन सरकारी सेवा में नियुक्त लोगों को और ज्यादा चाहिए। उन की बराबर यह शिकायत रहती है कि चूंकि अनाज और दूसरी वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि हो रही है इसलिए उनके वेतन बढ़ाये जायें।

आप जानते हैं कि देश के महात्मा मनीषी, सन्त बिनोवा जी ने सरकार से कई बार आग्रह किया है कि सरकार किसानों से जो नकद रूप में लगान वसूल करती है, उस के स्थान पर वह उचित लाभप्रद कीमत दर पर किसानों भूमि वालों से अनाज ही लगान के रूप में वसूल करे, और वेतन-भोगी कर्मचारियों को वेतन का एक भाग अनाज के रूप में दे। ऐसा करने से उन लोगों को भी राहत मिलेगी और हमारा प्रशासन भी ठीक ढंग से चलेगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बराबर सत्ता और आर्थिक व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के बारे में कहते रहे। ग्राम पंचायतों का गठन सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से ही किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि ग्राम पंचायतों के पास न कोई ताकत है और न कोई साधन है। वे केवल नाम की ग्राम पंचायतें हैं। इस लिए मैं चाहता हूं कि सरकार ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्ति और ऐसे साधन दे जिससे वे सुविधापूर्वक काम कर सकें।

पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति के बारे में आप की विशेष दिलचस्पी रहती है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। विरोधी पक्ष के सदस्य कहते हैं कि देश में कहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है। देश में बहुत बड़ा काम हुआ है बहुत विकास-कार्य हुए हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि केवल विकसित क्षेत्रों का ही ज्यादा विकास हुआ है—जो अमीर हैं वे ज्यादा अमीर हो गये हैं और गरीब लोग गरीब रह गये हैं। इस लिए गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था: अन टु दि लास्ट—सब से अन्तिम व्यक्ति सब से पहले जो सबसे पिछड़ा हुआ आदमी है जिस की हालत सब से दयनीय है, आज सरकार को सब से पहले उस की स्थिति में सुधार की व्यवस्था करनी चाहिए तभी देश का सम्यक विकास हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रताप सिंह नेगी (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं यह बजट पेश करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं इस बजट को समाजवादी बजट कहने के लिए तैयार नहीं हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समाजवाद के जिस लक्ष्य को जनता के सामने रखा था और जिस के बारे में घोषणायें की थी यह बजट उस के अनुरूप नहीं बना है।

मैं एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से आया हूं जिस ने इस देश को भरत जैसा मनस्वी और तेजस्वी महापुरुष दिया। मैं शकुन्तला-पुत्र भरत की जन्मभूमि से आया हूं। लेकिन आज उस क्षेत्र की क्या दशा है? जिस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हो, उस भरत की भूमि के विकास के लिए उस के उत्थान के लिए कोई ध्यान न दिया जाय यह अत्यंत खेद की बात है।

अभी विदेशी मुद्रा की कमी की रट लगा रहे थे और सभी लोग उस के लिए कह रहे थे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इन पहाड़ों का अन्वेषण करें और उस तरफ देखें तो वहां एक से एक सुरम्य स्थान मौजूद हैं। वहां फूलों की घाटी ऐसी है जिस में हजारों किस्म के फूल खिले हुए हैं और अगर वहां यातायात के साधन सुलभ कर दिये जायें तो मैं आप को यकीन दिलाता हूं वहां पर सैकड़ों विदेशी यात्री हर साल आएंगे। इस के अलावा वहां पर दूधाटोली एक ऐसा स्थान है जो 200 किलोमीटर पर फैला हुआ है और समुद्र की सतह से साढ़े चार हजार फुट की ऊंचाई से लेकर 9 हजार फुट तक की ऊंचाई उस की बगल में है। आप बर्फ पर खेलने के लिए स्विटजरलैंड जाते हैं या काश्मीर जाते हैं तो आप को कई मील चल कर बर्फ पर खेलने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन वहां आप को उस की बगल में ही ऐसा दृश्य नजर आयेगा कि आप बर्फ पर खेलने के लिए भी वहां जा सकते हैं।

[श्री प्रताप सिंह नेगी]

इस के अलावा जब यहां पर अंग्रेजों का राज्य था तो 1920-21 में उन्हें यह खतरा हुआ कि तिब्बत की ओर से कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला न कर दे, तो तब उन्होंने उस समय रेलवे लाइन के लिए यहां सर्वेक्षण कराया और कर्ण-प्रयाग तक खूटिया वगैरह बिछायी गई। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ता है कि जिस मंडल से मैं आता हूं उस गढ़वाल मंडल के चार जिलों में केवल आधा किलोमीटर रेल की लाइन है जब कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री आदि स्थानों को लाखों यात्री प्रति वर्ष जाते हैं और रेलवे को कोई घाटा उस में नहीं पड़ सकता है, अगर वहां रेलवे लाइन बना दी जाए। मुझे तो यह भी कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि अगर वहां लोगों के आने-जाने के साधनों की सुविधा हो जाए तो और बहुत से लोग वहां जाएंगे। फूलों की घाटी जिस में पूर्व जन्म में गुरु गोविन्द सिंह ने तपस्या की थी, वह हेमकुंड उसी इलाके में है।

सब से बड़ी बात तो यह है कि अगर हमारे दिलों के अन्दर भारत की रक्षा का ख्याल है तो क्यों कि चीन से आप के संबंध कोई अच्छे नहीं हैं, चीन आपके ऊपर झपट रहा है और वहां उस इलाके में बिल्कुल हम तिब्बत से मिले हुए हैं जहां चीन का प्रशासन है, वहां बाराहोती, नीति, माना, ज्वारहाट वगैरह बड़े-बड़े दर्रे हैं जहां से कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन स्थानों की तरक्की के लिए, इनके विकास के लिए कदम उठाए जायें। इनके विकास के लिए कदम नहीं उठाये जाने मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों के सब्र का प्याला लबरेज हो चुका है। हम इसलिए भी अलग राज्य की मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी राज्य सभा के चुनाव हुए। हमारे बराबर क्षेत्रफल का हिमाचल प्रदेश है। उस का क्षेत्रफल 55 हजार वर्ग-किलोमीटर और हमारा 51 हजार वर्ग किलोमीटर है। 34 लाख उन की आबादी है और हमारी 38 लाख आबादी है। लेकिन हमको एक भी प्रतिनिधि राज्य सभा में आज तक नहीं मिला जबकि हिमाचल प्रदेश के तीन सदस्य हैं। क्योंकि हमारे वहां उत्तर प्रदेश की विधान सभा में केवल 19 आदमी हैं। अब की साल दो कम कर दिए गए, पहले 21 थे। अब 19 ही रह गए। तो 425 की विधान में 19 आदमी किस तरह से अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं? यह हमारे साथ अन्याय है। परिसीमन अगर किया जाता है तो उस में क्षेत्रफल भी देखना चाहिए। आप को ताज्जुब होगा यह जान कर कि हमारे गढ़वाल मंडल में एक क्षेत्र के अन्दर 38 सौ वर्ग किलोमीटर का सफर करना पड़ता है जब कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में केवल 5 सौ वर्ग किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं हमारे साथ क्या बीत रही होगी। हमारे यहां पर सड़कें नहीं हैं, यातायात के साधन नहीं हैं। हमारी माताएं और बहनें तीन-तीन मील की उतराई से नीचे जाती हैं नदियों से पानी भरकर लाती हैं। यह हालत हमारी है। इस हालत को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे? जनता बेचैन है दुखी है। अगर यह होता कि हमारे यहां पानी न होता तो कोई बात थी। गंगा और जमुना जहां बहती हों, जहां रामगंगा हो, अलकनन्दा और भागीरथी हों वहां पानी न मिले, यह कितने आश्चर्य की बात है। यह केवल इसलिए कि उन के जल का उपयोग वहां नहीं हो पाता।

मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जिस क्षेत्र ने आज तक हमेशा देशभक्ति में अपने आपको आगे रखा है। आप को याद होगा पेशावर कांड का हीरा इसी गढ़वाल का पैदा हुआ वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली है जिसने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से साफ-साफ इंकार कर दिया था। उसके नतीजे के तौर पर उसे काले पानी की सजा भोगनी पड़ी थी। जो 28 हजार आपकी आजाद हिंद फौज में सारे देश के सैनिक थे, उस में से 3 हजार हमारे ही पर्वतीय जिलों के थे। आप समझ सकते हैं 56 करोड़ की आबादी के मुकाबिले में हमारी 38 लाख की आबादी है और हम 3 हजार के लगभग सैनिक आजादी की जंग में आपको देते हैं। तो यह हमारे अन्दर देशभक्ति की भावना ही तो होगी कि हम देश के लिए कुर्बानी

करना जानते हैं, हम देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं।

मैं ज्यादा न कहते हुए केवल यह निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि वह हमारे इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें, जहां अपार जल सम्पदा, अपार खनिज सम्पदा और सीमेंट के पहाड़ के पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन हम सीमेंट के लिए तरस रहे है, हम को सीमेंट नहीं मिलता है। हमारे यहां कोई उद्योग का साधन नहीं है उस के लिए। इसी प्रकार से जल-सपदा है, उस का कोई इस्तेमाल वहां नहीं हो पाता। जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी उन को मालूम होगा कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो संजीवनी बूटी द्रोण पर्वत से ही लाई गई थी। उसी द्रोण पवन के हम निवासी है। वह हमारे ही क्षेत्र में है। वहां हम जड़ी बूटियों का अनुसधान करें तो हम को मालूम होगा कि चरक ऋषि ने चरेक के डाडे में अपना आश्रम बनाया था जहां आज भी पुराने जमाने की जड़ी बूटिया मिलती हैं। मैं आप के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जाय।

15 hrs.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) . Mr Chairman, Sir, I have few very important suggestions to make My first suggestion is that our country's trade pattern should be made more liberal with the foreign countries considering the economic problems of the country Due to increase in oil prices in the world Government should cooperate with the consumers and producers countries and should seek to establish permanent arrangements. Government should ensure full production in industries, railways and agriculture. Highest priority should be given to overcome the economic difficulties created by the rise in prices. Immediate steps should be taken to establish fair prices for certain key goods and subsidies should be given to restrain the price rise and inflation caused as a result. Government should take steps to punish the hoarders and black-marketeers and profiteers. Goods should be labelled with the price at which they are to be sold; they should provide for the unit pricing by lagislation.

The Ministers and Government officials should work for a greater measure of social justice and for a better method of meeting the needs of the disabled at this difficult time.

Priorities should be given for improving facilities to children, particularly, for handicapped children Priorities should be given for provision of employment for unemployed youth. Prices of all commodities should be brought down so as to avoid revolution in the country.

Also priorities should be given for improving the facilities to children, particularly, to the handicapped children. Government should provide transport facilities for the public throughout the country.

Provisions of financial assistance to political parties to avoid corruption in elections should be made which would enable them to fulfil their parliamentary functions effectively Voting age should be reduced to 18 years Both the Lok Sabha and the Assembly elections should be held simultaneously throughout the country This may result in the savings of crores of rupees for spending in the country's Plan Either we should advance the Assembly elections or we should extend the time of Lok Sabha. Measures should be introduced to make further reforms in the law and improvement in administration of justice.

Banks having fixed deposit of Rs. 50 crores and above should be nationalised immediately in the national interest. My friends have spoken about the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. I say that the vishwakarmas having a population of five to six crores in the country should not be neglected and priority should be given to them in the matter of employment by providing for reservation of a certain percentage. There should be no excise duty imposed on small-scale aerated

[Sardar Swaran Singh Sokhi]

drink manufacturers. They should be exempted from the excise duty and they should be encouraged to produce more and more of healthy drinks.

Excise duty on foreign whisky, brandy and gin should be increased from 80% to 100% to compensate the relief given to small-scale drink manufacturers. This suggestion should be taken into consideration.

The prices of foodgrains paid to farmers for procurement should be at par with the imported foodgrains so as to boost the production Income-tax relief upto Rs. 6,000/- is quite reasonable and I agree with that. But the increase in postcards is quite unreasonable as that is the only media of communication of the poorer classes of the society.

Increase in population should be checked. I now come to a very important point When Spain could ask for increased prices for the ships, due to escalation of prices, I think it is proper that the Government of India should also ask Yugoslav Government to increase the prices of the wagons to be supplied by India or they should terminate the contract and thereby save Rs. 27 crores. The Finance Minister should look into the matter very seriously.

The Opposition parties instead of provocation should extend co-operation to the Government in checking bandhs, strikes etc. in the national interest.

Demonetisation would not help at this stage, but rather it would bring in more complications. Therefore, I am against it.

Inter-caste marriages should be encouraged rather than that things like what happened in Punjab should take place, namely that a person should be dismissed or should be discharged from service; and all the private and public institutions should be warned in this regard...

MR. CHAIRMAN: How does he correlate taxation with that?

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI: I am mentioning only the points. If you give me more time, I shall be able to elaborate them.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): During the budget discussion, the sky is the limit.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI: Now, I come to planning. We should have two-year plans instead of five-year plans for expeditious execution of projects and because of the price rise every year. Natural calamities should not always be blamed for failure to reach the target due to the inefficiency of the administrative machinery.

The Third Pay Commission's recommendations should be implemented without further delay, and their recommendations in regard to the class I officers also should be implemented.

As regards coal, the country has abundant coal lying at the pitheads, but transport is the main problem. Immediate attention should be paid to this matter.

No country should be allowed to have any base in the Indian Ocean, in the interests of peace in the sub-continent Our country should not lag behind in acquiring the latest war planes and nuclear weapons from whatever sources possible to defend ourselves in case of war with our neighbours

With these words. I support the budget.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढ़वाल). सभापति जी, आज ऐसे समय में जब कि देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, वित्त मंत्री जी ने जो संतुलित बजट पेश किया है, उस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस के बावजूद कि हमारे विरोधी दलों के कुछ मित्रों ने जिस प्रकार से इस की आलोचना की है और गरीबों व पिछड़े वर्गों की दुहाई देकर कहा है कि गरीबों पर टैक्स लगा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस

विषय में न्याय नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं—वित्त मंत्री जी ने जो रैफिजरेटर, एयर-कंडीशनर्ज, टेलिविजन सेट्स जैसी वस्तुओं पर जो कर लगाया है, क्या इन वस्तुओं का इस्तेमाल कमजोर वर्ग करता है? अभी कल ही वित्त मंत्री जी ने राज्य सभा में दोहरी-मूल्य-नीति का उल्लेख किया। यह निश्चित है कि इस से हमारी आमदनी और अधिक होगी और जो एफ्लुएन्ट सैक्शन आफ सोसायटी है, उस से और अधिक पैसा इन के लिये प्राप्त कर सकेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम आय वाले लोगों के लिये जो आप ने 6 हजार रुपये व्यक्तिगत आय तक छूट दी है, वह अपर्याप्त है, इस को यदि आप 10 हजार कर दे तो मैं समझता हूं कि आज के महगाई के जमाने मे यह उचित ही होगा। पोस्ट कार्डों पर, जिसे आम तौर से हिन्दुस्तान का गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, जो 5 पैसे की वृद्धि की है, इसको अवश्य समाप्त किया जाना चाहिये, भले ही हमारी आय मे इससे कुछ घाटा हो। इसकी पूर्ति के लिए आप शराब और पर और टैक्स लगा दीजिए, मनोरजन और आमोद-प्रमोद के साधनो पर टैक्स लगा दीजिए, किन्तु इस प्रकार की चीजों पर टैक्स लगाना उचित नही होगा।

सभापति जी, हमारी इस महगाई और भुखमरी का बहुत बड़ा कारण यह है कि देश की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष 2.2 प्रतिशत आबादी बढ़ रही है। जिसके कारण हमे करीब 20 लाख टन अतिरिक्त गल्ला हर साल उन के लिए बढ़ाना पड़ता है। इस लिये मैं समझता हू कि आबादी की रोक-थाम के लिये हमे विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

काले धन का यहां पर बहुत उल्लेख किया गया है। अनुमान है कि 7 हजार करोड़ रुपए से लेकर 10 हजार करोड़ रुपए तक का काला धन हमारे देश में इस समय चल रहा है। यह बात, जैसा कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है हमारी अर्थ-व्यवस्था समानान्तर स्थिति पर पहुंच गई है। मैं समझता हूं अगर काला धन इस्तेमाल करने वालो को अवसर दिया जावे तो हमारे पब्लिक सेक्टर मे जो 105 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 5052 करोड़ रुपया लगा हुआ है, उन 105 पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को वे लोग दो बार खरीदकर बेच सकते हैं इस काले धन की बदौलत। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह काला धन कितना महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश मे कर रहा है। इसलिए मैं समझता हू इसकी रोक-थाम बहुत ही आवश्यक है।

मेरी राय मे डीमानेटाइजेशन या डीवैल्युएशन से इसका कोई हल निकलने वाला नही है। इस सबध मे मैं एक सुझाव मत्री जी को देना चाहता हू और वह यह है कि आप 3 महीने बाद, चार महीने बाद एक तिथि निश्चित कर ले और उस तिथि तक सरकार नये डिनामिनेशन के नोट छाप दें तथा यह घोषणा कर दे कि अमुक तिथि तक जिनके पास जो रुपया है उसको उस रुपए से परिवर्तित कर ले। इस प्रकार सारा पैसा बाहर निकल आयेगा और मैं समझता हू इससे मुद्रा-स्फीति तत्काल रुक जायेगी।

दूसरे – जैसा अभी हाल मे देश के 130 प्रमुख अर्थ-शास्त्रियो ने प्रधान मत्री जी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे उन्होने कहा कि जो इस समय अर्थ-व्यवस्था हमारे देश मे है उसको ठीक करने के लिए वर्तमान करसी का आशिक रूप से डीमानेटाइजेशन किया जाये और ऐसा डीमानेटाईजेशन करने के लिए उन्होने एक उपाय भी सुझाया है कि जिसके पास 1 हजार रुपया है वह उसमे से 700 रुपए अपने पास रखले और बाकी 300 रुपए के वह लबी अवधि के नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट या दूसरे रूप से परिवर्तित करले। इसके लिए भी आप एक निश्चित तिथि रख सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ और सुझाव उन विशेषज्ञो ने प्रधान मत्री जी को दिए हैं जिनमे एक प्रधान मत्री के कार्यालय से संबंध एकोनामिक कमेटी की बात भी है यदि उन पर कारगर उपाय किए गए तो इन्फ्लेशन की जो प्रवृत्ति है, उसमें बहुत कुछ रुकावट हो सकती है।

[श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली]

डिफेंस पर जो दो हजार करोड रुपए का हमारा खर्चा है वह मैं समझता हू न केवल उपयुक्त है बल्कि यदि आवश्यकता पडे तो उसमें वृद्धि करने की भी जरूरत हो सकती है क्योंकि देश की सुरक्षा हमारे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। यदि देश ही नही रहेगा तो फिर हम कहां रहेंगे, हमारी आने वाली पीढियां कहा रहेंगी ? इसलिए सुरक्षा के लिए जो प्राविधान किया गया है वह सर्वथा उपयुक्त है।

इसके पश्चात् मेरी राय मे दूसरा सर्वोच्च स्थान कृषि को मिलना चाहिए। तीसरे स्थान पर मैं समझता हू पेट्रोलियम की खोज और उसका उत्पादन वार-फुटिंग पर हाथ में लेना चाहिए तभी हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते है मुझे दो चार मिनट और चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हू, अपने दक्षिणपंथी दोस्तो से नही पीलू मोदी साहब यहा पर है, बाकी चले गए। जो हमारे प्रगतिशील विचारो के दोस्त हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हू कि वे कोई ऐसा फार्मूला इजाद करें ताकि एम्प्लायर एम्प्लाई के संबंध इस प्रकार के हो सके जिससे पाच साल तक हडतालो की रुकावट कर सकें। मैं आकडे प्रस्तुत कर सकता हू कि रेलवे मे 1972-73 मे 19 32 करोड रुपए का रेवेन्यु लास हुआ हड़तालो के कारण। इसी प्रकार पब्लिक सेक्टर मे जो हमारे पाच स्टील प्लाट्स चलते हैं उनमे अकेले 1973 मे 293 854 करोड रुपए का नुकसान हुआ है। हैवी इजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में पिछले तीन सालो मे 48 46 करोड रुपए का नुकसान हुआ है। आई०डी०पी०एल० की जो तीन यूनिट्स है उनमे से दो यूनिट्स—एन्टीबायटिक प्रोजेक्ट, ऋषिकेश और सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंटस प्लांट, हैदराबाद—मे 1972-73 मे 414.32 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हडतालो के कारण पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स मे 1971, 1972 और 1973 के 6 महीनो में 60 लाख दियाडी (मैनडेज) का नुकसान उठाना पड़ा है।

इडियन एयर लाइस की हालत तो आपको मालूम है। वहां पर 24 11-73 और 21-2-74 के बीच में 276 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहां पर लाक आउट के कारण 14,442 एम्पलाईज को जो उसमें काम करते थे अपना वेतन न मिलने के कारण 209 लाख रुपए का नुकसान उठाना पडा।

इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंन्ट एम्प्लाईज जो हैं उनको जो ओवर-टाइम पेमेंट दिया गया है वह 1970-71 और 1972-73 के बीच में 123.81 करोड़ दिया गया है। तो अनप्रोडक्टिव चीजो पर जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसपर उसको रोक लगानी होगी।

यहां पर हाउसिंग मिनिस्ट्री के मंत्री शास्त्री जी बैठे हैं। उनको मालूम है कि दिल्ली में मकानों की कितनी तंगी है। बहुत से लोग मकानो की सब-लेटिंग करते हैं। बहुत से एम्प्लाईज ऐसे हैं जोकि अपने पिता के मकान मे रहते हैं जबकि गवर्नमेंट सर्विस मे हैं लेकिन फिर भी वे दिखाते है कि हम किसी और जगह रह रहे हैं। इस प्रकार से लाखो रुपए का नुकसान हर सरकार को उठाना पड रहा है। मुझे एक दो मिनट और चाहिए।

हमारे देश मे 30 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन मे भी नीचे अपना जीवन व्यतीत करते है। इसमे हमारे उत्तर प्रदेश का जो पहाडी इलाका है वह गरीबी की उस रेखा के सबसे नीचे की सीढ़ी पर है। उस के विकास के लिए वहा की स्थानीय परिस्थितियो को देखते हुए वहा के साधनो को लेकर विकास करने की आवश्यकता है। वहां पर कैश क्राप्स मे आलू और फल तथा सब्जियां होती हैं परन्तु दुर्भाग्य है कि वहां का सारा रा-मैटीरियल, वहां की सारी फारेस्ट वैल्थ, सारी मिनरल वेल्थ मैदानो मे चली जाती है और उसकी रोक-थाम के लिए सरकार ने कोई भी उपाय नही निकाला है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके लिए कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।

अन्त मे मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हू कि 1961 की गणना के अनुसार 3.15 करोड़ भूमिहीन मजदूर हमारे देश मे थे और 1971 मे उनकी संख्या बढ़कर 4.56 करोड़ हो गई।

जब भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो फिर आखिर हमारी प्लानिंग, हमारी समाजवाद की बातें, हमारी प्रगतिशील बातें, गरीबी के नीचे के तबके को ऊपर उठाने की बातें कहां जा रही हैं? यह दुर्भाग्य की बात है कि भूमिहीन मजदूरों की संख्या इस प्रकार बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। इस संबंध में मैं केरल की सरकार को जो उन्होंने हाल में केरल एग्रीकल्चरल बिल पास किया है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं समझता हूं इसके माध्यम से वे वहां पर भूमिहीन मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे। मैं समझता हूं भारत सरकार भी इस प्रकार का कोई प्रविधान करेगी ताकि सारे देश में भूमिहीन मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत किया।

श्री तुलाराम (घाटमपुर) सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं यहां पर वित्त मंत्री महोदय के बजट प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं उन्होंने समय के हिसाब से मुनासिब बजट रखा है। इस समय देश में चीजों का अभाव और महंगाई है। आयकर में 5 हजार रुपए सालाना आय की छूट को उन्होंने जो 6 हजार रुपए कर दिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ साथ मैं सामान्य प्रशासन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल भ्रष्टाचार का बोल बाला है। पहले नीचे के स्तर पर ही भ्रष्टाचार था लेकिन अब वह भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर भी पहुंच गया है। मुझे तो कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनको सुनकर मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनका सिर नीचे हो जायेगा।

चूंकि इस देश के 70 फीसदी आदमी खेती पर निर्भर करते हैं इसलिए खेती के संबंध में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। खेती के लिए जरूरी है अच्छा बीज, अच्छी खाद, पानी और अच्छे औजार। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने किसानों को अच्छे बीज दिए और अच्छे औजारों की व्यवस्था की लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि खेती के लिए सिंचाई और खाद की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस साल मैंने देखा कि यूरिया जिस की कीमत 51 रु० है बाजार में ब्लैक मार्केटियर्स द्वारा 100 रु० बोरी के हिसाब से किसानों को बेचा गया। पिछले साल 1972-73 में सूखा पड़ा और उसकी वजह से पानी की कमी हुई लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में यह देखा कि पानी की कमी के बावजूद, बिजली की कमी के बावजूद, दिन में बिजली 6 बजे से 12, 1 बजे तक सारा को दी गई। लेकिन इस साल किसान को बिजली नहीं मिली। तीन-तीन, चार-चार दिन तक बिजली नहीं आयी जिस से गेहूं की खेती की बड़ी दयनीय दशा हो गई। इसलिये खेती की पैदावार इस साल बहुत गिरेगी। क्योंकि इस वर्ष तुषार भी पड़ा उस की वजह से नुकसान हुआ, अरहर और चने का काफी नुकसान हुआ और दूसरे पानी न मिलने की वजह से गेहूं की फसल को, जिस में 6, 7 पानी लगने चाहिये, दो पानी भी मुश्किल से नहीं मिल पाये।

एक बात प्रोक्योरमेंट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जब आप प्रोक्योरमेंट की बात सोचें और कहें तो आप को सोच लेना चाहिये कि किसान का खर्चा कितना बढ़ गया। आप ने 76 रु० के भाव से किसान से गेहूं लिया और आज बाजार में गेहूं 160 रु० प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस तरह से कीमतों में जो फ़र्क होता है वह किसान की तरक्की और संतुलन की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि चूंकि खेती से संबंध भोजन का है उस में तथा दूसरी खाने की वस्तुओं में बहुत मिलावट हो रही है। रोज अखबारों में से निकलता है, लेकिन लगता है सरकार उन को नहीं पकड़ती है और रोकने का कोई समुचित प्रबंध

[श्री तुलाराम]

नहीं करती है। सरकार के जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स हैं मैं ने अपनी आंखो से देखा कि जब वह बनिये की दुकान पर पहुंचते हैं तो उन की खातिर से भी ज्यादा खातिर तवाजेह होती है। इस की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। भोजन के मामले में एक बात और कहनी है, सब तरफ गल्ले की सप्लाई का शोर मचा हुआ है और यह सिर्फ शहरो तक ही सीमित है। आम देहात मे औसतन लगभग ढाई छटाक एक परिवार को शकर देते हैं जब कि शहर में एक व्यक्ति को एक एक किलो देते हैं। इसी तरह से शहर मे सभी लोगो के लिये गल्ला देते है लेकिन देहात का जो छोटा किसान और मजदूर है उस की तरफ आप की निगाह नहीं है। इस तरह से शहर और देहात से भेदभाव करना एक समाजवादी सरकार के लिये मुनासिब नही है।

एक बात मैं पुलिस के सबंध में कहना चाहता हूं। जो पुराने जमींदार हैं वह पुलिस से मिले हुए हैं और अगर कोई गरीब आदमी जमींदार का खेत जोतने के लिये नही जाता है तो उस आदमी को पुलिस द्वारा डरवाते हैं। थाने में ले जाकर और हर थाने में 25 रिवाल्वर और 50 कारतूस रहते हैं इसलिये किसी गरीब के साथ एक रिवाल्वर दो कारतूस का इल्जाम लगा देते हैं और किसी के साथ एक रिवाल्वर और एक कारतूस का झूठा इल्जाम लगा कर उन गरीब लोगो को जेल भेजते और दूसरी तरह से हैरान किया जाता है। यह नही होना चाहिये।

हमारी कांस्टीट्यूऐंसी में कचौसी स्टेशन पर ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है और उस के न होने के कारण हर साल वहां पर लोग ऐक्सीडेंट्स से मरते हैं। मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें।

आप ने जो मुझे समय दिया उसके लिये आप को बहुत धन्यवाद।

SHRI P. R. SHENOY (Udipi): Sir, though the budget for 1974-75 presented by the respected Finance Minister, Chavanji, cannot be called a poor man's or even common man's budget, yet I support it for its brighter aspects. The budget has made a realistic assessment of the economic situation in the country and has proposed certain rational steps to check the economic deterioration that is taking place in the country. Hence I welcome the budget.

The crores of poor people in this country can be made happy to a large extent if they are assured of at least two square meals per day. In this context, I am sorry the budget has not spelt out the need for import of sufficient quantity of foodgrains from abroad. This country was never self-sufficient in foodgrains. We were all the while importing foodgrains. We committed a mistake when we declared that we were self-sufficient in foodgrains and did not require any more food import This is not a realistic assessment of the food situation Taking both normal and abnormal years into consideration, we are not yet self-sufficient in foodgrains Therefore, there must be a policy of importing foodgrains well in advance. Every year we say that we will not import foodgrains but at the end of the year we pay a heavy price and import foodgrains This is not a good policy. If we want to save foreign exchange, we should not do so by putting restrictions on the import of essential commodities We should put more restrictions on luxury goods like fine cotton used for superior cloth. We must put a further check on petrol consumption. Petrol is practically wasted today. There must be a ceiling on the use of private cars by the executives of the private as well as public sector. There must also be a ceiling on air travels by these executives. In this way, we can save a lot of petrol. There should not be any saving of foreign exchange at the expense of the poor man because this Government stands for the poor man.

Coming to price rise, of course it is accepted by all now that the main reason is deficit financing. The second reason is black money. The third reason is this loose talk of demonetisation without actually doing it. Because of the fear of demonetisation, people with black money buy all

the goods available in the market and thereby raise the prices of the commodities. Therefore, there should not be any loose talk of demonetisation. If Government wants to demonetise, it should do so immediately. Otherwise, it should say that for the next three or four years, there will not be demonetisation.

It is a sad thing that defence expenditure is going up year after year. After the establishment of Bangladesh, our defence expenditure should have gone down. Instead of that, it has gone up. We must somehow reduce the defence expenditure or at least the wastages in defence expenditure should be identified and stopped in future.

I conclude by making a specific suggestion about a proposed excise duty. This Government is for the small man. It has levided excise duty on all aerated water units using power. This is not fair. There are several units using 3 or 5 HP. I request the Finance Minister to exempt all aerated water units using 5 HP or less.

श्री मधु लिमये (बांका): मैं आशा करता था कि इस बजट के जरिये वित्त मंत्री सरकार के कामकाज में जो नीतिहीनता और दिशाहीनता दिखाई दे रही थी और जो अन्तर्विरोध प्रकट हो रहा था उसको सुलटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन खेद है कि इस बजट ने इस अन्तर्विरोध को मिटाने का जरा भी प्रयास नहीं किया है बल्कि इस बजट में सरकार के जो दिवालियेपन की नीति है उसी का इजहार होता है। जब से चौथी योजना प्रारम्भ हुई अर्थ व्यवस्था में सभी क्षेत्रों में ह्रास होता जा रहा है। विगत एक साल में अनाज की कीमत चालीस प्रतिशत से अधिक बढ़ी है और जब से गरीबी हटाओ का जमाना शुरू हुआ है क्या कर वृद्धि और क्या घाटे की अर्थ व्यवस्था, दोनों में बड़ी तेजी से सरकार प्रगति कर रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 का बजट पेश किया गया। उसके तीन साल पहले यानी चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में कुल मिला कर 244 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टैक्स लगाए गए। लेकिन बाद के चार वर्षों में नई कर वृद्धि 840 करोड़ रुपये की हो गई। घाटे की अर्थ व्यवस्था का जहां तक सवाल है 1967, 1968 और 1969 में यानी चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में 544 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई लेकिन बाद के चार वर्षों में जब से गरीबी हटाओ का नारा बुलन्द हुआ 2110 करोड़ रुपये का डिफिसिट फाइनेंसिंग किया गया। उसी तरह जहां तक चौथी योजना का सवाल है उसका यह लक्ष्य बनाया गया था कि हर साल राष्ट्रीय आमदनी में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। लेकिन उसके पहले चार वर्षों में क्या हुआ? पहले वर्ष में तो 5.2 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद यह दर लगातार गिरती गई और तीसरे वर्ष में चौथी योजना के राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि सिर्फ 1.7 प्रतिशत की हुई और चौथे वर्ष में 0.6 प्रतिशत की ही हुई।

जहां तक पांचवीं योजना का सवाल है इसका मसविदा विगत दिसम्बर मास में पेश किया गया था। लेकिन यह जो बच्चा पैदा हुआ यह जन्म से ही मरा हुआ पाया गया है क्योंकि इसके आधार बिल्कुल निकम्मे साबित हो गये हैं, जहां तक प्लानिंग कमिशन का सवाल है वह निरर्थक और बेमतलब हो गई है। मैं सभी आधारों की चर्चा नहीं करना चाहता। केवल दो बुनियादी बातों को लेता हूं। इस के पृष्ठ संख्या 73 पर एक आधार यह दिया गया है:

"Efficient management of the food economy so as to avoid large scale food imports".

मैं कहना चाहता हूं कि इधर चार पांच महीनों में अनाज के मामले में सरकार की नीति और कार्यान्वयन में कोई बुनियादी परिवर्तन हुए हों, इसके आसार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के नेता और मंत्री जब आमने सामने हम से मिलते हैं पार्लियामेंट के बाहर तो सरकार की जो स्वीकृत नीतियां हैं उनकी खुलकर आलोचना करते हैं—

एक माननीय सदस्य. ऐसी बात नहीं है।

श्री मधु लिमये: झूठ मत बोलिये। चापलूसी और असत्य यह आज सत्ताधारी दल का आधार बन गया है, लाबीज में एक बात कहना और यहां दूसरी ठीक नहीं है। व्हीट टेक ओवर की नीति गलत है यह केवल आज ये नहीं कह रहे हैं दस बारह महीने पहले भी कांग्रेस के प्रमुख लोग ऐसे थे जो कहते थे कि गेहूं के सरकारीकरण की नीति इसलिए गलत है कि हमारे पास

श्री मधु लिमये

न कोई बल है और न हमारे द्वारा ठीक से इंतजाम किया जा सकता है। उन में नक्सली भी थे। वे खुलकर कहते थे। मैंने पूछा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को क्यों नहीं कहते तो लोग कहते थे कि हमारी हिम्मत नहीं है। सत्य अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर प्रतिक्रियावादी होने का सिक्का लगाया जाएगा। डर के मारे असली मुद्दों पर अपना मत अभिव्यक्त करने से कांग्रेसी नेता और मंत्री हिचकिचाते हैं। ये ठीक सरकार की राय नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के बारे में इस सरकार की जो नीति रही है उसका कांग्रेस के अन्दर जबर्दस्त विरोध होते हुए भी खुल कर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस संदर्भ में मैं आप से कहना चाहता हूं कि गेहूं के मूल्यों का जब सवाल आया उस समय हमारे लोगों ने मांग की थी कि सौ रुपये में खरीदने की मूल्य नीति होनी चाहिए। इसका जबर्दस्त विरोध किया गया लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो स्वयं कांग्रेसी हैं, जिनके पास अच्छी खासी जमीन है क्या उन लोगों ने निर्धारित दामों पर यह लेवी देने का प्रयास किया था? एक एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जिससे पता चलेगा कि साधारण किसान के लिए एक कानून, एक मापदंड और अपने बड़े लोगों के लिए दूसरा मापदंड। क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश पंजाब तक बड़े काश्तकारों का गेहूं सीधा ट्रकों पर लाद कर बम्बई की मंडियों में साढ़े चार सौ रुपये क्विंटल तक बेचा गया है जबकि साधारण किसान को 76 रुपये से लेकर 80-82 रुपये तक गेहूं बेचने के लिए आप बाध्य करते थे? आप विदर्भ के हैं? आप क्या इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कपास और ईख के बारे में इसकी खरीद की नीति को अपनाया।**

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi): He is naming the Chief Minister. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Order, order. All of you please sit down.

Mr. Limaye, when you are making an allegation against a person who is not a Member of this House and who cannot defend himself, that is not allowed under the Rules. That is not proper; that is wrong.

श्री मधु लिमये : * * *

MR. CHAIRMAN : Nothing of this will go on record. It will be expunged. It is undignified. It is derogatory to the parliamentary procedure. Please don't make personal allegations against anyone. (*Interruptions*).

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): On a point of order, Sir. You were kind enough to bring to the notice of the hon. Member the true position of the Rules. In spite of that, he has been persisting in saying that he has been stating the truth. Is it not defiance of the Chair? Should he continue to go no making allegation?

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

श्री मधु लिमये : मैं सही बात कर रहा हूं। सही बात सुनने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप तो ट्रेड यूनियन में रहे हैं। मझे चापलूसी की आदत नहीं है।

मैं कह रहा था कि पांचवीं योजना का यह जो आधार है कि अनाज का वितरण और उसकी खरीद हम बढ़िया ढंग से करेंगे, जैसा आपने किया है इसका मानने का भी कोई आधार नहीं है। इस आधार पर यह जो इमारत खड़ी गई है यह बिल्कुल बेबुनियाद होने के कारण टूटने लगी है।

दूसरा आधार बताया है :

"Tightening of foreign exchange control to check leakages through under-invoicing of exports and over-invoicing of imports and the diversion of remittances from Indians abroad through unofficial channels."

मैं एक अरसे से इस सरकार से कहता रहा हूं कि भारतीय लोगों के द्वारा विदेशों में जो पैसा कमाया जाता है—और उसका अनुपात इन दस वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है—आज वह तस्करी के लिए एक

**Expunged as ordered by the Chair.

मालूम बता गया है इस सरकार की पंचवर्षीय योजना का आधार है कि वह विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकेगी, लेकिन—मुझे फिर इन बातों को कहना पड़ता है, क्योंकि इन बातों से इन्कार नहीं किया गया है—जब सरकार के बड़े लोग ही स्मगलरों के सम्राट के साथ मुलाकात करेंगे, और उन से एक करोड़ रुपया लेंगे, तो फिर वित्त मंत्रालय के तहत कौन अफसर ऐसा है, जो विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकेगा ?

इस आरोप का किसी ने भी खंडन नहीं किया है कि स्मगलरों के सम्राट, कुली मस्तान, के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात हुई है। किसी ने इसका खंडन नहीं किया है, और कर भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की एक्जीक्यूटिव के सदस्यों ने इस बात की ताईद की है कि इस तरह की मुलाकात हुई थी। सिर्फ तस्वीर खींचने का प्रयास असफल रहा। वह एक करोड़ रुपये के बदले तस्वीर लेना चाहता था। (व्यवधान) मुझे ज्यादा बाध्य करेंगे तो मैं और कुछ कह दूंगा। इसलिए इसको छोड़ दीजिए।

आज सवेरे बिहार का सवाल आया था। बिहार में विस्फोट क्यों हुआ ? उधर के माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह नक्सलाइटस ने किया, आर०एस० एस० ने किया, गुंडों ने किया। लेकिन असली बात यह है कि बिहार भारत का सब से गरीब इलाका है। उस में 25 प्रतिशत से अधिक लोग भूमिहीन खेतिहर हैं, और दस साल के अन्दर खेतिहर मजदूरों का अनुपात 9 प्रतिशत बढ़ा है।

सरकार राज्यों को जो अनाज देती है, उसमें किस तरह का न्याय है ? मेरे 18 मार्च के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पश्चिमी बंगाल ने 25.70 लाख टन अनाज मांगा और उस को 18.88 लाख टन दिया गया केरल ने 13.48 लाख टन अनाज मांगा और उसको 10.16 लाख टन दिया गया, महाराष्ट्र ने 36.83 लाख टन अनाज मांगा और उसको दिया गया 24.18 लाख टन। और बिहार को ? उसने 17.40 लाख टन अनाज मांगा और उसको सिर्फ 4.40 लाख टन दिया गया, यानी केन्द्रीय सरकार ने उसकी आवश्यकता को पच्चीस प्रतिशत से कुछ थोड़ा ज्यादा पूरा किया।

अगर सरकार समझती है कि वह गोली और सेना के बल पर जन-असंतोष को कुचल डालेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि न केवल बिहार में, बल्कि समूचे देश में आग लगेगी और उस में ये लोग भी खत्म हो जायेंगे और लोकतंत्र भी खत्म हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आप भी खत्म हो जायेंगे।

श्री मधु लिमये : हम को तो ये लोग वैसे ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। हमारा भविष्य कोई महत्व की बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आग लगेगी, उसमें ये लोग खत्म हो जायेंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र उसमें खत्म हो जायेगा, यह एक चिन्ता का विषय है।

15.43 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

पांचवी योजना में कहा गया है कि हर साल औसत पब्लिक सैक्टर आउटले 7,450 करोड़ रुपये होगा और इस बजट से पता चलता है कि सरकार केवल 4,364 करोड़ रुपया वर्तमान दामों के आधार पर लगाने वाली है। पंचवर्षीय योजना के पहले साल से ही पब्लिक आउटले का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, और बढ़ते हुए दामों के कारण जो भी पूंजी लगाई जायेगी, उस में कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है

हालांकि नियोजन पर मेरा विश्वास है, लेकिन विगत वर्षों में सरकार ने जिस ढंग से योजना आयोग को चलाया है, उस को देखते हुए मेरी स्पष्ट राय है कि सरकार वर्तमान योजना आयोग को समाप्त कर दे, और उस के लिए उस ने जो 13.70 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में मांगा है, वह उसकी भी बचत करे, क्योंकि इस योजना आयोग और योजना मंत्रालय से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बजट में मैंने उन चीजों पर टैक्स लगाया है, जिन का इस्तेमाल अमीरों के द्वारा किया जाता है। लेकिन कौन नहीं जानता है कि सरकार किसी भी रूप में टैक्स लगाये, सारा इन्तजाम और व्यवस्था ऐसी है कि अन्ततोगत्वा साधारण जनता पर ही उस का बोझ पड़ता है

[श्री मधु लिमये]

सरकार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कहा है कि हम लोग सीधे टैक्सिज से आमदनी बढ़ायेंगे। उस ने पंचवर्षिय योजना के प्रारूप में घोषणा की है

> "The additional tax effort envisaged in the Fifth Plan period—the yield from direct taxes is anticipated to improve to 3.8% of the GNP."

That is improvement by 0.67%.

लेकिन इस बजट में मंत्री महोदय ने सीधे टैक्सिज को घटाया है। फिनान्स बिल के वक्त में अपना टेबल पेश करूंगा और यह साबित करूंगा कि जिनकी आमदनी दस हजार से बीस हजार रुपये है, उनको मंत्री महोदय ने बहुत मामूली किस्म की राहत दी है, लेकिन उन्होंने बड़े लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर राहत दी है।

उन्होंने दलील यह दी है कि अगर हम टैक्स को घटायेंगे, तो उस से शायद टैक्स की चोरी कम हो जायेगी। लेकिन लोग इस के इतने आदी हो गये है कि मंत्री महोदय के प्रोपोजल का टैक्सों की चोरी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह मर्ज एक अरसे से चली आ रही है।

सरकार के पास कोई राष्ट्रीय आय नीति नहीं है। मैं एल०आई०सी० के वेज बिल के आंकड़े देख रहा था। एल०आई०सी० में जो क्लास वन और क्लास टू के 13,000 कर्मचारी हैं, उन से से एक एक की वार्षिक औसत आमदनी 1 32 लाख रुपये है। अगर उन के तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों को भी मिला दिया जाये, तो भी उन की औसत वार्षिक आमदनी, 9,000 रुपये है। यह कौन-सा सामाजिक न्याय है? मैं श्री चव्हाण से पूछना चाहता हूं कि भारत में कितने किसान ऐसे हैं, जिन पर पांचवीं वर्षीय योजना की सफलता निर्भर करती है, उनकी 2,000 रुपये की भी वार्षिक आमदनी है। इस सरकार की आय नीति में सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों पर सरकार ने योजना को सफल बनाने का सब से अधिक बोझ डाला है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

डीजल का सवाल हो, या कैरोसीन आयल, लौबिकेटिंग आयल या फर्टिलाइजर हो, उन में से एक भी चीज, जो खेती की तरक्की के लिए आवश्यक है, निर्धारित दाम पर नहीं मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में उनके दाम दुगने से भी अधिक है। जब तक सरकार वितरण की व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी, तब तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है।

जहां तक कपड़े का सवाल है, विगत साल मंत्री महोदय ने कहा कि कपड़े के दाम बहुत बढ़ गये हैं और उन के बारे में कुछ करना चाहिए। एक साल हो गया, लेकिन अभी तक कपड़े के बारे में सरकार की कोई सकलित नीति, इनटेग्रेटिड पालिसी, नहीं बन पाई है। मैंने सुना है कि नियंत्रित कपड़े का अनुपात बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन उस को पांच दस प्रतिशत बढ़ाने से क्या होगा? सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत जो मोटे और मध्यम श्रेणी का कपड़ा नियंत्रित दाम में पैदा किया जायेगा, उस का इस्तेमाल देश की जनता करेगी और फाइन और सुपरफाइन कपड़ा केवल निर्यात के लिए रखा जायेगा?

मैंने इस सदन में पहले भी एक बार कहा था कि सरकार सूडान और ईजिप्ट से चार लाख बेल्ज लांग स्टेपल काटन मंगाती है, लेकिन उसने एक थ्रेले का निर्यात भी नहीं किया। जब अमरीका जैसा अमीर देश एक लाख बेल्ज से संतुष्ट था, जापान केवल दो लाख बेल्ज मंगाता था, लेकिन सारा निर्यात के लिए। लेकिन इस देश के अमीरों को अच्छी पोशाक पहनाने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके हर साल चार लाख बेल्ज लांग स्टेपल काटन विगत आठ-नौ वर्षों में मंगवाई है। व्यवधान हो, इस साल नहीं आया। लेकिन दस साल जो 8 सौ करोड़ रुपया चला गया क्या आप का यह कहना है कि उस का अर्थ-व्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ? इस 8 सौ करोड़ रुपये से आप फर्टिलाइजर मंगाते या और कोई चीज मंगाते जब आप ने निर्यात की बात की है तो मैं आप को एक बात कहना चाहता हूं। अमेरिका से ये चीजें क्यों मंगाते हैं? कल मैं सिंगापुर गया था। यह टीचर गैस सैल जो वहां चलाया गया अमेरिका से मंगाया गया था। सिंगापुर से गोलीकांड था, टीचर

गैस बनी । मैं इस को टेबल पर रख रहा हूं । आप देखिए । क्या अमेरिका से इन चीजों को मंगवाना चाहिए या जिस से उत्पादन बढ़े उन चीजों को मंगवाना चाहिए ? मैं अहमदाबाद और बड़ोदा भी गया था । वहां मैंने देखा, तिकेलिंग गैस जिस का इस्तेमाल हुआ अमेरिका से उसको मंगवाया गया था और मेरा ख्याल है कि बिहार में भी 4 सौ 5 सौ शेल कल जो, विस्फोटित किए गए थे उन के बारे में भी मुझे टेलीफोन पर पता चला है कि सारा माल अमेरिका से मंगाया गया था । तो आप अमेरिका से दमन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, दमन के सामान अमेरिका से मंगाते हैं ? क्या यही आधार है अमरिका के साथ दोस्ती रखने का या कुछ ऐसी चीजें आप वहां से मंगवायेंगे जिन से उत्पादन बढ़ेगा ?

एक ही बात और कह कर मैं खत्म करता हूं । यहां वर्ल्ड बैंक की रपट के बारे में चर्चा हुई । आप एकदम चुप रहे, जैसे आप का हमेशा तरीका होता है क्योंकि आप संसद को तो कुछ समझते ही नहीं, संसद को विश्वास में ले कर कुछ बहस करना, विचारों का आदान-प्रदान करना यह तो आप का कभी तरीका होता नहीं, हमेशा तकनीकी जवाब दे कर आप समय काटने का काम करते हैं । इस तरह से काम नहीं चल सकता । वर्ल्ड बैंक को छोड़िए, मैं पूछता हूं क्या यह बात सही नहीं है, मैं इसी के आधार पर कहता हूं, अनाज के बारे में, विदेशी सहायता के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में और तेल इत्यादि के बारे में जो वर्तमान स्थिति है उस को देखते हुए क्या यह बात सही नहीं है कि उस रिपोर्ट में जिन बातों की चर्चा की थी वह ज्यादा वास्तविकता के करीब है बनिस्बत प्लानिंग कमीशन के इस प्रारूप के ? इसलिए सत्य बोलने से भारतीय लोग कब से डरने लगे ? सत्य कोई बोलता है तो कहा जाता है कि यह भारत विरोधी है । हम लोग स्थिति को बदलें, वास्तविकता को बदलें । दूसरों पर कीचड़ उछालने के पहले हम लोगों को अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने का काम करना चाहिए । इतना ही मुझे कहना है ।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur): What are you going to do with the tear gas shell? Tomorrow he may come with a bomb; he is a privileged Member. Why have you allowed him?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not allowed him to lay it on the Table.

श्री पीलू मोदी : ऐसे घबरा न जाओ । वह तो खाली है । सिर्फ बम जैसा देखने में लगता है, बम नहीं है ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANTRAO CHAVAN): This is the fifth day that we have been hearing the very interesting speeches of hon. Members in this House and I must thank them for the very keen interest that they have taken in the Budget that was presented here.

I find from all the speeches that I have been privileged to listen here that practically all the aspects of the Budget, all the aspects of the economy, have been very carefully considered in the Debate.

Naturally, as has always been the reality, the Budget has been receiving criticism from certain sections of the House whereas other sections have approved of the Budget and some of them have given critical support to it.

I would certainly try to deal with some of the general points that were raised in the Debate. Even though I may wish to go into the details of the various points raised by them, it is physically not possible for me to deal with all of them. So, Members would be kind enough to excuse me if I may not be able to deal with those points in detail, but I can certainly assure the House that they will certainly be attended to.

I find that there are two or three lines of criticisms that have been levelled against this budget. The Leader of the Communist Party (Marxist) who initiated the debate has, as expected, described the budget as pro-monopoly, anti-people and reactionary. I said 'as expected', because I could not have expected anything else. Naturally, everything that we decide in

[Shri Yashwantrao Chavan]

always anti-people and "pro-monopolist". According to you, this is the only way in which you can look at the budget. The other Members, Shri Indrajit Gupta, particularly, on behalf of the Communist Party of India described the budget as a theory of surrender—this is a surrender to tax evaders; surrender to big business and a surrender to rural rich. I must say that I do not expect this sort of adjectives that have been used here because, they are not true. They do not stand the test of an examination.

Naturally, all Members have raised a very pertinent point and they wanted to examine this budget so as to see how best that is going to deal with the major problems of our economy today. I may be excused if I were to repeat the arguments that I have made the other day. Whatever may be the basic realities of the economy according to them and also basic realities of the economy according to me. Let us examine how far this budget goes to deal with the problems of inflation, price rise, deficit financing and also the problem which is most important, namely, the economic growth of this country.

This is the test on the basis of which one could certainly say that this budget is useful, or not useful reactionary or progressive or whatever one would like to say.

I would like to make a humble claim that this is a very right way of examining this budget and there is nothing wrong about it. After the budget is introduced, the next day how can you expect a hundred percent solution to the problem of price rise and inflation? That cannot be done. The budget has tried to deal with the problem and, ultimately, you will have to take the economy as a package. The economic situation of a country depends upon political factors and, naturally, depends upon economic and social factors as well. Many factors come into making of an integrated picture of the economy. I cannot claim that all these problems can be solved quickly. It is true that problems are there—there is inflation; there is price rise; it is accepted that deficit financing is, of course, there. Increased money supply is also the result of inflation. This is a situation for which we will have to find a solution. What is the solution for this? Giving orders only to roll back or stabilise the price is not going to stop this. Inflation is there, deficit financing is there. One has to find out a way for it. We should try to find out the reason why we are going in for deficit financing.

16 hrs.

Shri Madhu Limaye has just mentioned certain figures about deficit financing. I certainly accept the position that during the last four years there was considerable deficit financing. But I would like to say that there might have been still more deficit financing had we not taken some of the important steps that we took during the last four years. Even then, I would like to point out how it was necessary and how we were forced to have deficit financing.

Some hon. Members from my side of the House mentioned that I had the dubious distinction of having created a record in raising resources. I did not know whether I had that distinction or dubious distinction. But the fact is that I did that, and I do not want to deny that. It is better that I myself say this instead of somebody else trying to examine it. In 1971-72, the budget raised Rs. 251 crores, in 1972-73 it raised Rs. 183 crores, in 1973-74 it raised Rs. 290 crores and in the present budget estimates, we have made an attempt to raise Rs. 212 crores. So, the total comes to about Rs. 936 crores.

SHRI MADHU LIMAYE: It is really more.

SHRI K. NARAYANA RAO: That is an index of our progress.

श्री मधु लिमये : आप ने पैट्रोल प्राइसेज़ को नहीं जोड़ा है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने बजट के द्वारा क्या पेश किया है, उसकी जोड़ा है।

श्री मधु लिमये . यही तो चालाकी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो कुछ हम कहते हैं वह चालाकी है और आप जो कहते हैं वह होशियारी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : होशियारी और चालाकी एक ही बात है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप हिन्दी के विद्वान हैं, आप सोचिये इस के बारे में।

श्री राम सहाय पाण्डेय : वित्त मंत्री को चतुर होना आवश्यक है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : फर्क तो थोड़ा है ही।

In addition to this, I would like to say that we made the borrowing programme very substantial. For example, in 1972—74 the average that we raise as public borrowing was about Rs. 415 crores; it was average for three years. The total borrowing programme including that of the Centre, the States and such other public sector agencies as the State Electricity Board has gone up from Rs. 480 crores in 1970 to Rs. 1020 crores in 1973-74. I do not want to burden the House with all these details. What I am trying to point out is that despite all these efforts at raising public money and public borrowing and also raising resources, we had to resort to deficit financing, even though we wanted through the budget estimates to reduce it as far as possible. In 1971-72, the actual deficit financing was Rs. 521 crores, in 1972-73 it was Rs. 882 crores, and in 1973-74 it was Rs. 650 crores, and during the three years, it comes to nearly Rs. 1752 crores. But it is much more important to know why it was that we had to resort to deficit financing. From the figures that I have got, the most important items on which we had to resort to deficit financing during these three years were : refugee relief, defence, natural calamities—in one year, it was Rs. 220 crores, in another year it was Rs. 145 crores and in the third year it was Rs. 40 crores—and then pay revision which is Rs. 236 crores in this year, and dearness allowance accounting for Rs. 100 crores, and food subsidy to the extent of Rs. 121 crores additional to what we have provided for in the budget. I am merely reading out the headlines for these items which forced us to resort to deficit financing.

Merely because we have provided certain smaller amounts in the budget, could we have said 'No' in the case of refugee relief or defence or natural calamities or pay revision or dearness allowance ? Ultimately, the Government has to face and I think the Parliament has to face and the country has to face the situation as it emerges. We just cannot order the actual life to go along the path that we have indicated in the budget. Certain situations arise, and we have to meet the situations. Therefore, one should see the deficit financing in that perspective. This seems to be the reality of the situation during the last three or four years. The point is how we are going to meet this situation Ultimately it comes to this question only My own answer, as far as this budget is concerned, is that we can meet all these difficult situations of deficit financing and money supply. It was said that money supply is more because there is more of government spending. Conceded. But I have explained to you why Government had to spend more. Naturally, when it becomes dangerous, the proportion of money supply, when there is no relationship between production and money supply —you cannot hold money supply as such responsible—when money supply is not in proportion to the rise in production, rate of production, certainly it becomes unbalanced, certainly it becomes a dangerous position.

So ultimately it comes to this position that unless we strengthen the forces of production, unless we strengthen the process of growth in the economy of the country, these problems cannot be dealt with effectively. This is the basic answer to this question. Even if we go on repeating the problems and trying to apportion blame on each other, a solution cannot be found.

[Shri Yashwantrao Chavan]

The basic solution to the problem is to find out which are the areas which need to be supported, strengthened, planned properly and implemented properly to see that there is more growth. It is very well known which are the areas where we need to do these things. I would like to claim that in this budget we have done this in regard to the core sector of the economy. If you read again. Part A of my speech, you will find that in the case of agriculture, steel, power, irrigation, which are the most important areas of growth in the economy, we have made sufficient provision in this particular matter. If you want, I can certainly go into some of the details of it.

I was surprised at an argument in the speech of my hon. friend, Shri Surendra Mohanty. If I may quote him, he said :

> "Is the budget growth-oriented? Long-term objectives have been given precedence over the concern for the immediate problems. Therefore, the plan investment from the actual level of Rs. 4,171 crores in 1973-74 has been pushed up to Rs. 4,769 crores."

I was expecting some better argument than this. If at all you are going to plan, planning means precedence to long-term objectives over the immediate needs.

I was very pleased to listen to the remark made by Shri Piloo Mody the other day, not in the discussion of the budget but while he was asking a question regarding drawals from IMF. When we said that we are withdrawing certain funds from IMF, he asked : here are you going to make use of it? Are you going to use it for consumption purposes or are you going to use it in investments which will give us growth? It was a very pertinent point. I appreciated that point. I would like to say that when we are making provisions in the budget, we have to think in terms of growth. It means you have to select some areas where you can utilise or invest those monies in the sense that it would lead to growth in the country. These are the basic areas. These are the areas where we have to bring about growth.

I, therefore, claim that this budget has certainly made a reasonable effort to see that the growth forces, the production forces, of the economy are strengthened.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) जितना आप ग्रोथ में देते हैं, उस का ठीक से यूटिलाइजेशन होता है या नहीं, उतना ग्रोथ होता है या नहीं, इस को कौन देखेगा। हर साल हम यही सुनते हैं। 120 करोड़ रुपया गण्डक में दिया, 3 लाख एकड़ में सिंचाई होती है — पैसा कहां गया ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं आप को इस के बारे में बतलाऊंगा।

I was trying to make the point that as far as the basic outlays of the budget are concerned, they are production-oriented, they are growth-oriented. It is in this sense that I say that this budget is certainly trying to deal with the problems and the basic questions of inflation and deficit financing.

The other question is about the taxation proposals. Some members have approved of them, some have not, some have found fault with them. In these proposals, I have been guided by certain principles that we have also laid down. I would like to read again a part of the speech that I made in 1971 in which, I had indicated, myself, certain broad principles. The first principle is that the tax structure must be simplified and rationalised in such a way that the burden of assessment for the assessee as well as the tax collector and the opportunity for evasion are minimised. Secondly, the overall burden of tax must be distributed among different sections of the community in such a manner that in the process there is appreciable scaling down of the concentration of economic power and reduction of inequalities in income levels. Thirdly, the incidence of fresh impost should not as far as possible disturb the general level of prices of essential goods.

These are the general principles. Whatever taxation efforts have been made in this budget have been made on the basis of these principles.

There are two types of tax efforts—direct taxes and indirect taxes. My claim is that the relief which has been given is investment oriented.

Shri Madhu Limaye raised the question whether the tax payers in this country have become honest enough to take advantage of this and to make investment, implying that everybody in this country, at least these tax payers in higher brackets has become so dishonest that he has gone beyond the scope of any correction or redemption. I am not so pessimistic about it. I quite agree that there are hard boiled tax evaders and it is difficult to reform them. But there are some new people who are coming into these brackets, younger generation; I have hope in them. They are equally concerned with the national economy.

SHRI R. S. PANDEY : At least the salaried people are 100 per cent honest.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : We have given them relief...(*Interruptions*). If he feels he can give certain proposals he is welcome to do that and they will be considered. This relief is given practically all along the line, small, middle and the higher income.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The relief is not even.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : That can be argued and replied to. It can be explained also. That is a different matter. But this type of relief in direct taxes is meant for investment. It is not going to be used for further consumption, and therefore the taxation proposals that are made here are of a non-inflationary nature.

SHRI MADHU LIMAYE : You have not related it to investment.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : The relief is such that a man who gets it will be inclined to invest it.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : Unless you say that, if he invests, he would get certain relief it would not be automatically invested.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : I do not know whether you are a lawyer unless you indicate certain incentives for investment. A man will not invest is a proposition which I am not prepared to accept. A man who legally saves certain money, what will he use it for ? Ostentatious consumption ? He will not. My expectation is that he will not do so. If he has got illegal money or unaccounted money, he cannot invest it and he is bound to resort to ostentatious consumption. But if a man saves money legally he will be interested in investing it in long term deposits in the Bank; he can invest it in units or in small industry or in some other industry. So it is a saving which is bound to be invested.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : He will invest it for cornering foodgrains and other essential commodities.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN :, I am not inclined to agree with you, when you say that whatever investments are made are for anti-social purposes.

The indirect taxes have been based on certain selectivity approach. A large majority of members had accepted them. They are well selected and they are not commodities of mass consumption.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about the post-card ?

SHRI R. S. PANDEY : Less love letters.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : I am not an expert on that matter. Possibly you can give an opinion on that .... (*Interruptions*).

Therefore, my claim is that the taxation proposals in their very nature, are not inflationary. Some hon Members have said

[Shri Yeshwantrao Chavan]

that this Budget has completely by-passed problems of inflation and problems of growth. This is not true. It has directly dealt with these problems.

Sir, I, certainly will be able to give information about Plan outlays. Some Members did make that point whether our claim of helping growth is consistent with our Plan outlays. Certainly, I would like to claim that this is according to the Plan provisions indicated therein.

I would now like to pass on to some other important areas of economy; mentioned by hon. Members.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): What is the rationale behind imposition of excise duty on tooth paste and increase in the price of post-card?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I have explained it. I thought you might have read this in the newspapers this morning. I do not want to repeat the same thing. But, I am expected to give the rationale behind this. I have to give the rationale. we have discussed this many times on the floor of this House. This is one of the industries, which is making huge profits. Your point is that the excise duty will be passed on to the consumer. Possibly, it will. Normally, these people try to do that, and they will do that. I do not know--possibly they will try to do that. That is no reason why we should not impose excise duty. Certainly, they will also think about the possibility of consumer resistance to such things. If there is consumer resistance, I would certainly welcome that because people in this particular industry are making very huge profits. We cannot allow this to go on. One can say that their profits should be taxed, which is being done. Not that they are exempted from taxation.

SHRI SAMAR GUHA: What about post-card?

SHRI PILOO MODY (Godhra): If you nationalise the tooth paste industry and de-nationalise banks, it will be alright.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: What a heavy bargain you are trying to make!

Sir, Mr. Samar Guha is constantly asking about the post-card. The Telegraphs and Postal Department have got their own problems. This is a service which, certainly, is meant for the people. But, it has become a costlier service. Every year, they are incurring loss.....

SHRI PILOO MODY: and very inefficient.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: These commercial departments have to become self-sufficient. They must be able to increase their own resources and utilise them for further development.

SHRI H. M. PATEL: Not a commercial department, but, a social service department.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: Even then, it has to find resources for its development. You cannot forget that. I considered this question of reducing the postal rates. I discussed this matter with the Minister of Communications There were some suggestions in this regard. But, it becomes rather very difficult to accept them. When we increase the price of other articles, for example, the inland letter card, which has gone up from fifteen paise to twenty paise, if we keep down the price of the post-card where it was, there will be more incentives for the people to make use of post-cards than inland letter cards.

SHRI ATAI BIHARI VAJPAYEE: In the case of the post-card, the increase is 50%. This is too high.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: You should not go by percentages. The base is smaller, and therefore, the percentage looks a little higher. This is a simple thing. Let us not consider this in terms of percentages.

SHRI VASANT SATHE: You can give concession, as far as post-card is concerned.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: As you know, I have still to cover a gap of Rs. 125 crores.

SHRI VASANT SATHE: You can tax some other luxury items.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I was saying that I shall pass on to certain specific subjects mentioned by hon Members. Most important of these is black money.

It has been constantly mentioned in the debates, in Question Hour, calling attention notices, etc. Even in this debate, many people said that I have not dealt with the problem of black money It is true that I have not used the term 'black money' as such. But most important measures have been taken to deal with this problem. I would like to tell the House how we look at this problem. Ultimately, what is black money? It is unaccounted money, which is the result of tax evasion If we are to deal with this problem of unaccounted money, we will have to find out what is the genesis of it and what are the mechanics of creating it. One will have to deal with t fundamentally. Our approach is that the problem of black money can be dealt with only if we try to meet successfully the problem of tax evasion Of course, there is another aspect of it. The shortages of commodities is also responsible for creating black money We will have to deal with the problem of producing on a mass scale the commodities of mass consumption. I think this problem has been very carefully examined by the Planning Commission. They are considering a certain report. When their report comes out, we will have to take decisions about encouraging mass production of all these essential commodities and also proper distribution of those commodities. That will take care of the problem of price rise as well.

About tax evasion, it can be dealt with in two or three ways. What are the remedies suggested so far? The remedies suggested so far are, we must deal with the problem of agricultural income, which is being made use of for tax evasion. Secondly, it was suggested that black money is being invested in certain properties.

AN. HON. MEMBER: What about contributions to election funds?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: You have also fought elections and we have also fought elections.

Some people are speaking as if we have not done anything about the problem. We passed a law in 1972 to deal with the problem of transfer of under-valued properties. The Bill was introduced in 1972. It went to the Select Committee and passed through the various stages. That Bill has provided a certain time lag. The whole process has started now. Under that Act, when the properties are transferred, they are registered and every registered deed is examined by the income-tax department. According to the test laid down in the Act, when they find that there is reason to believe that a certain property has been under-valued at the time of transfer, they are supposed to start action. In the last few months, they have issued notices to 3669 persons in all the important cities There is a long list of them. Of course, the law has provided certain procedures in this matter. They have to give notice. The man gives his reply and it is examined They are supposed to produce certain evidence After that, the income-tax officer is supposed to pass an order So far orders have been passed only in 20 cases, but their total value comes to more than Rs. 25 lakhs. I am sure as time proceeds, this will accelerate further.

Coming to the question of agricultural income, there is always a complaint and a very right complaint as to what we are doing about taxing the agricultural sector. The Raj Committee had made certain recommendations. We accepted the most important of the recommendations, which concerned the Central Government.

Those people who have non-agricultural income, if they have agricultural income,

[Shri Yeshwantrao Chavan]

the two incomes should be clubbed and they should be taken into account together. We accepted this suggestion in the last budget. I am sure this is one of the sources of evasion of taxes which has been plugged in a way.

Then there is the question of creating fear in the mind of the tax evader. As hon. Members know, particularly those who are Members of the Select Committee, this Bill is under consideration by the Select Committee for more than a year. They have gone to the different cities of the country and taken evidence

SHRI MADHU LIMAYE: Of the tax-evaders?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I am sure when this Bill becomes law, it will certainly be a harsh and very severe law. Those who take the risk of evading taxes will certainly be treated more severely than criminals, because, in the present context of things, we have a tendency in our country to treat economic offences as fashionable offences and so richer people can get away with these things In the new Act we are making economic offence a more serious offence so that the culprits will be punished pretty severely under the law

At the same time, it was necessary to find out what other things can be done. There was an incentive for tax evasion, namely, economic incentive at least this was what was talked about. We did not want to give any scope for any argument on that line. So, we considered the Report of the Wanchoo Committee on this matter and decided to accept this recommendation Let us see what the effect of it is.

So, the problem of black money has been attacked from all sides. Of course, one very constant question is: what about demonetisation? As I said before, which I would like to say again, Government do not intend resorting to demonetisation, because it is not one of the permanent methods of dealing with this problem. What we can do continually, permanently, basically and fundamentally is being done and whatever requires to be done will be done in future.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): What is being done?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: This is like hearing the Ramayana for the whole night and then asking what is the relationship between Sita and Rama.

SHRI PILOO MODY: How can you talk about black money without talking about the election fund?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I am talking about what we have done and what we are going to do. You have only to talk

SHRI PILOO MODY I know that you are dealing with both-black money and election fund.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: If you are serious about this point, certainly we can discuss it some time. I can discuss it with Shri Limaye too.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara): What is the tax arrears of Shri Mundhra since 1965?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: If you put a question, I will answer it.

AN HON. MEMBER: What about Biju Patnaik?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: You can better ask him.

SHRI PILOO MODY: Does it mean that you will ask Mr. Mundhra and Shri Mohanty will ask Mr. Patnaik and thus parcel out black money?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: If I want that information, there is no necessity for me to ask him.

Coming to tax arrears, I would like to say that during the last three years we have made very serious efforts for attack-

ing this problem. While on 31st March 1972 the amount outstanding was Rs. 805 crores, on the 31st December 1973, after one year and nine months, it has come to Rs. 714 crores, which means that more than Rs. 100 crores of these arrears have been recovered.

As on 31st March, 1973, there were 660 cases where gross arrears exceeded Rs. 10 lakhs in each case. The comparative position of these cases, as on 31st December, 1973 is that the number has become 626. I am only indicating the trend of the effort that we are making in this matter.

Then, the hon. Member, Shri Indrajit Gupta, asked me a question as to what we are doing about perquisites and he wanted to know exactly what steps we are taking about it. There are two aspects of this matter. One is regarding the valuation of the perquisites and the other is, how far lavish these perquisites are enjoyed by the employees and reflected in their income.

So far as the first aspect is concerned, the valuation of the perquisites has been modified In the case of free accommodation, at present, it is 10 per cent of the employees' salary and now it will be 12 per cent. In the case of free furnished accommodation, it has been raised from 12-1/2 per cent to 15 per cent. In the case of motor car provided by the employer, it is Rs. 300 per month as against Rs. 150/- per month. In the case of big motor car, it is Rs. 400 per month as against Rs. 250 per month. In the case of where motor car is owned and hired by the employer but running and maintenance expenses are borne by the employee, it is Rs. 100 as against Rs. 60 per month. In the case of big motor car, it is Rs 150 as against Rs. 100 per month.

As far as the other aspect is concerned, after making certain studies, we have found that unless the assessments of the Companies are correlated with the assessments of the Directors and highly paid employees, it will not be possible to ensure that the deterrent provisions which are provided in the Act are implemented. We have, therefore, decided to create special cells for centralisation of cases of Companies, Directors and their senior executives. In pursuance thereof, necessary instructions were issued to the Commissioner of Income-Tax in July, 1973 for centralisation of such cases.

Recently, a study was undertaken and it was revealed that substantial additions have been on account of perquisites allowed by the Companies in the assessments of Directors and senior executives as well as the Companies. With the release of additional staff which used to do routine work of finalising the assessments of salaried employees getting an annual income of Rs 18,000, it will be possible for us to concentrate on such cases so as to get better results in future.

One question that is constantly asked is as to how far the deficit financing that I have provided for in the Budget, that is Rs. 125 crores, is realistic. I would like to say that as far as the assessment of the present situation is concerned, it is realistic. But, at the same time, I cannot guarantee that there will not arise occasions for additional expenditure as we proceed in the year. Our effort will be to see that we try to contain the present gap as it exists

Shri Atal Bihari Vajpayee has raised two or three points and I certainly would like to say, if I can, something about those points. He has asked whether the money that we will get as a result of Russian deal, by way of sale of Russian wheat here, is mentioned somewhere or not. This is one of the points that he made The other point that he made was that there was less and less provision for minimum needs programme including provision for drought-prone areas.

As far as Russian wheat is concerned, I would like to point out to him that this

[Shri Yeshwantrao Chavan]

is mentioned in the Explanatory Memorandum on page 58, paragraph 46, under 'Other items (Net)'. I will read it out:

> "The estimates here show the net effect of transactions occurring under sundry deposits, suspense, remittances, etc. heads not dealt with earlier. The Revised includes credit of Rs. 741.40 crores on account of U.S. rupee balances deposited with the Government of India in the Public Account as non-interest bearing deposits. The next Budget includes credit of Rs. 200 crores from sale proceeds of two million tonnes of wheat loaned by the USSR."

He had mentioned it in such a way as if we were trying to put it under carpet and get away with it. It is mentioned in the Budget.

About the provision for drought-pron areas programme, he said that only Rs. 6.3 crores had been allotted for this programme this year. I think he was not properly informed by his adviser. According to the Budget Estimates for 1974-75, it is Rs. 22 crores. It is somewhat lesser than what we provided last year, but it is Rs. 22 crores and not Rs. 6 crores as he thinks.

About minimum needs programme, a provision of about Rs. 200 crores has been made in the State Plans for 1974-75 under the minimum needs programme for social and community services. After transfer of some of these services to the State sector, to the States' account, the provision in the Central Plan for 1974-75 will compare very favourably with the last year's provision also on this particular point of minimum needs programme.

I am mentioning some of these detailed things because some detailed points were raised by hon. members.

My friend, Shri Dinesh Singh, who is not present now, had raised the question of performance of the public sector. I certainly would like to let him know that, as far as public sector is concerned, it is showing some good signs. (*Interruptions*) It is turning the corner; there is no doubt about it.

SHRI PILOO MODY: It depends on where the corner is.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: In the case of public sector, I would like to mention to him, the Planning Commission has appointed a Group which is going into the examination of the functioning of the public sector thing, and I must say that this Group has certainly done a very good piece of work; they have certainly found out the areas which need our special attention; they have certainly given some sort of a new impetus to the working of the public sector thing. In the case of public sector, their planning for the next year appears to be very encouraging; the way they are going to produce more and the likely profit they are going to make, I would like to say that this year, 1974-75, will be a very important year in the life of public sector undertakings as such; this is a most important area whose growth and whose vitality we as a nation are interested in.

One of the four constructive suggestions that Shri Piloo Mody made was: get rid of the public sector. Look at the way he looks at the economy. A very important suggestion as a result of his speech was: get rid of this and reduce the tax! Of course, he made two very important suggestions. Spend more on the rural sector. That is what we are planning to do. Spend more on agriculture. That we have been doing. He asked me to read some article of Shri Giri Lal Jain. I would like to tell him that agriculture has always been a very important sector in all our planning and it will continue to be so. Naturally, we will select those areas where it will give strength to our economy as a whole and that we will certainly try to do.

As far as the public sector is concerned, I think I have given certain facts.

Shri Dinesh Singh also mentioned about exports. As far as exports are concerned, I would like to point out to him that we

have concentrated our efforts on exports this year. Our exports are going to be the major area in which we will try to find a solution for our problem of balance of payments particularly, as a result of the rise in the prices of crude oil and other important items like fertilisers and steel. Our major answer will have to be found in an increase in our exports and a strategy is being worked out. The Commerce Ministry and the Planning Commission are looking into the matter and I have every confidence that they will certainly work out a programme which will help us increase our foreign exchange income. These are some of the major points I could deal with in reply to the debate here.

As far as I see, the problem is full of difficulties. I do not want to take a complacent view of the matter. There is certainly, as I said, a very challenging situation in the country. As a matter of fact, for the last four years, it has been a continuous period of difficulties and challenges but with faith in ourselves as a nation, we can certainly overcome these problems successfully.

Sir, I have done

16.43 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL), 1974-75

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, I will put the Demands for Grants on Account (General), 1974-75 to the vote of the House.

Now, the question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the order paper, be granted to the President, *on account* for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 106."

The motion was adopted.

[*The Motions for Demands for Grants on account (General), 1974-75 which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 1—Department of Agriculture.

"That a sum not exceeding Rs. 27,20,000 on Revenue Account be granted to the President, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of 'Department of Agriculture'."

DEMAND NO. 2—Department of Agricultural Research and Education.

"That a sum not exceeding Rs. 1,30,000 on Revenue Account be granted to the president, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of 'Department of Agricultural Research and Education'."

DEMAND NO. 3—Agriculture

"That a sum not exceeding Rs. 13,04,65,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 61,32,08,000 on Capital Account be granted to the President, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Agriculture'."

DEMAND NO. 4—Fisheries

"That a sum not exceeding Rs. 1,23,59,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 21,30,000 on Capital Account be granted to the President, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of 'Fisheries'."

---

*Moved with the recommendation of the President.